



**CHARMINAR®**  
PAINT BRUSH  
Cell : 9440297101

वर्ष-28 अंक : 198 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) **आखिन कू.7 2080 गुरुवार, 5 अक्टूबर-2023**

# आप सांसद संजय सिंह गिरफ्तार

**दिल्ली आबकारी केस में ईडी ने 10 घंटे छापेमारी की, इसी केस में मनीष सिसोदिया जेल में हैं**



दिन भर पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर ले जाती ईडी टीम।

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उनके दिल्ली वाले घर पर बुधवार सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची थी। 10 घंटे तक चली इस छापेमारी के बाद गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि करीब 7-8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे थे। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इस केस में मनीष सिसोदिया जेल में हैं। ईडी की कार्रवाई को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा- इस केस में 1000 रेंड पड़ चुकी हैं। संजय सिंह के घर पर कुछ नहीं मिलेगा। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और वे जानते हैं कि वे हारेंगे। ये उनकी हताशा भरी कोशिशें हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएगा,ईडी, सीबीआई जैसी सभी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। इस बीच, दिल्ली में बीजेपी ने आप के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा के कार्यकर्ता 'अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है', नारे वाले पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों की मांग है केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

**\* सौरभ भारद्वाज बोले- यह एक काल्पनिक घोटाला है**

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा- यह एक काल्पनिक घोटाला है जिसमें पिछले 15 महीने से छान-बीन चल रही है। कम से कम 1 हजार जगहों पर ईडी और सीबीआई छापेमारी कर चुकी हैं, लेकिन कहीं से भी 1 रुपया बरामद नहीं हुआ। संजय सिंह के घर ईडी की छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा - संजय सिंह अड़ाणी के मुद्दे पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं और इसी वजह से उनके आवास पर छापेमारी की गई है। केंद्रीय एजेंसियों को पहले भी कुछ नहीं मिला और आज भी कुछ नहीं मिलेगा।

**\* कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा- बीजेपी भय-आतंक का माहौल बना रही**

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा- यह (बीजेपी) सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर जोर-जबरदस्ती, दमन, भय और आतंक का माहौल प्रकराओं के खिलाफ और उन नेताओं

## 15 घंटे में में 13 बार हिली नेपाल की धरती

**अभी टला नहीं है भूकंप का खतरा!**

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। नेपाल के पश्चिमी हिस्से में आए मंगलवार को भूकंप के बाद सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। क्योंकि नेपाल में मंगलवार दोपहर दो बजे से लेकर बुधवार की सुबह पांच बजे तक लगातार धरती का हिलना जारी रहा। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक इन 15 घंटों में नेपाल के पश्चिमी इलाके में बने एपिसेंटर से 13 बार नेपाल के अलग-अलग हिस्सों में भी धरती का कंपन महसूस किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरीके से लगातार प्रत्येक घंटे में औसतन चार की तीव्रता से ज्यादा वाले भूकंप नेपाल में आ रहे हैं, वह खरों की ओर इशारा भी कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरीके के आफ्टर शॉक्स लगातार बने हुए हैं और तीव्रता बढ़ती है तो निश्चित तौर पर खतरा भी बड़ा हो सकता है। जिसका उसका असर नेपाल के साथ-साथ भारत के अलग

अलग हिस्सों समेत दिल्ली-एनसीआर तक में देखा जा सकता है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में पहली बार मंगलवार को भूकंप दो बजकर 25 मिनट पर 4.6 की तीव्रता का आया था। उसके ठीक 26 मिनट बाद यानी दो बजकर मिनट पर नेपाल में जबरदस्त तरीके की धरती हिली। उस वक्त भूकंप की तीव्रता 6.2 की आंकी गई। यही वह दो भूकंप के झटके थे, जिन्हें दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में जबरदस्त तरीके से महसूस किया गया। आंकड़े बताते हैं कि नेपाल में इन दो बड़े झटकों के बाद एक नियमित अंतराल पर लगातार बुधवार की सुबह तक भूकंप के झटके आते रहे। इन दो झटकों के बाद मंगलवार दोपहर बाद तीन बजे से लेकर चार बजे के अंतराल में तीन और भूकंप के झटके नेपाल में महसूस किए गए। इन तीनों झटकों की रिक्टर स्केल पर तीव्रता साढ़े तीन की आंकी गई।

## राष्ट्रपति मुर्मू बोलीं : देश के विकास के लिए सुरक्षा जरूरी

संसाधनों के सही इस्तेमाल पर निर्भर करती है प्रगति



राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) पाठ्यक्रम को संबोधित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि भारत की सुरक्षा चिंताएं क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण से परे हैं और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ऊर्जा और साइबर सुरक्षा से निपटने के कल्याण के अन्य आयामों को शामिल करती हैं। वह यहां राष्ट्रपति भवन में 63वें राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी) पाठ्यक्रम के संकाय और पाठ्यक्रम के सदस्यों को संबोधित कर रही थीं। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक माहौल गतिशील है और कई चुनौतियां पेश कर रहा है।

**‘भू-राजनीतिक परिस्थिति ने बदल दिया सुरक्षा परिदृश्य’**

उन्होंने आगे कहा, तेजी से बदलते हुए भू-राजनीतिक माहौल में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। भू-राजनीतिक गतिशीलता ने सुरक्षा परिदृश्य को बदल दिया है। राष्ट्रीय और वैश्विक मुद्दों की गहरी समझ रखने की जरूरत है। हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है, बल्कि साइबर युद्ध, प्रौद्योगिकी-सक्षम आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी नई सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है।

**‘अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लागू करने की जरूरत’**

मुर्मू ने कहा कि व्यापक अनुसंधान पर आधारित ज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ‘आपको वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए ऑर्टोफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) के इनोवेटिव एप्लिकेशंस का पता लगाने की जरूरत है। वास्तव में, सरकारी एजेंसियां और कॉर्पोरेट क्षेत्र को इन चुनौतियों की पहचान करने और उनसे निपटने के लिए हाथ मिलाने की जरूरत है।’

**‘क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण से परे हमारी सुरक्षा चिंताएं’**

मुर्मू ने जोर देकर कहा कि जिस तरह से वैश्विक घटनाएं सामने आ रही हैं, हम किसी भी तरह की स्थिति और संकट से निपटने के लिए विश्व स्तर पर सक्षम और भविष्य के लिए तैयार आत्मनिर्भर होने के महत्व को तेजी से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज हमारी सुरक्षा चिंताएं क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण से परे हैं और इसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से निपटने वाले कल्याण के अन्य आयाम शामिल हैं।

### ‘प्रगति और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा जरूरी’

राष्ट्रपति ने कहा कि सशस्त्र बलों की भूमिका पारंपरिक सैन्य मामलों से परे भी बढ़ी है। उन्होंने कहा, ‘यह स्पष्ट है कि जटिल रक्षा और सुरक्षा माहौल में भविष्य के संघर्षों के लिए अधिक एकीकृत बहु-राज्य और बहु-एजेंसी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।’ मुर्मू ने कहा कि प्रगति और विकास के लिए सुरक्षा और रक्षा जरूरी है।

उन्होंने कहा कि किसी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने पास उपलब्ध संसाधनों, विशेष रूप से अपने मानव संसाधन का कितने प्रभावी ढंग से उपयोग करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सिविल सेवा और रक्षा सेवा दोनों के अधिकारियों को देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में संवैधानिक ढांचे के बारीक बिंदुओं को समझना चाहिए।

THE LARGEST CIRCULATED AND READ HINDI DAILY IN TELANGANA & ANDHRA PRADESH

# स्वतंत्र वार्ता



epaper.vaartha.com



**नोकास**  
काफ़ सिरप  
**FREE**  
Inhaler  
**For Trade Enquiry : 8919799808**

प्रधान संपादक - डॉ. गिरिश कुमार संधी हैदराबाद नगर पृष्ठ : 16 मूल्य : 8 रुपये

### केंद्रीय कैबिनेट ने तेलंगाना में 900 करोड़ रुपये के आदिवासी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के मुलुगु में 900 करोड़ रुपये की लागत से सममक्का-सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को चुनावी राज्य तेलंगाना के अपने दौर के दौरान मुलुगु में विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने एक समारोह के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार मुलुगु में एक केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, जिसका नाम आदिवासी देवी सम्मक्का और सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। इस पहल के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मैं तेलंगाना के लोगों को उनके प्यार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि इस साल दिसंबर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की राज्य में ज्यादा राजनीतिक उपस्थिति नहीं है। इसलिए पार्टी आक्रामक तरीके से राज्य में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी पिछले एक सप्ताह में दो बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। जिससे पता चलता है कि भाजपा राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करने को लेकर कितनी उत्साहित है, जहां मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और विपक्षी कांग्रेस के बीच द्विध्रुवीय है।



नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के मुलुगु में 900 करोड़ रुपये की लागत से सममक्का-सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर को चुनावी राज्य तेलंगाना के अपने दौर के दौरान मुलुगु में विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने एक समारोह के दौरान कहा था कि केंद्र सरकार मुलुगु में एक केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करेगी, जिसका नाम आदिवासी देवी सम्मक्का और सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। इस पहल के लिए 900 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मैं तेलंगाना के लोगों को उनके प्यार के लिए आभार व्यक्त करता हूं। बता दें कि इस साल दिसंबर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की राज्य में ज्यादा राजनीतिक उपस्थिति नहीं है। इसलिए पार्टी आक्रामक तरीके से राज्य में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी पिछले एक सप्ताह में दो बार तेलंगाना का दौरा कर चुके हैं। जिससे पता चलता है कि भाजपा राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज करने को लेकर कितनी उत्साहित है, जहां मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) और विपक्षी कांग्रेस के बीच द्विध्रुवीय है।

## 10 अक्तूबर को विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे बिधूड़ी

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी 10 अक्तूबर को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होंगे। 10 अक्तूबर को रमेश बिधूड़ी विशेषाधिकार समिति के सामने अपना बयान दर्ज कराएंगे। बैठक के एजेंडे के अनुसार, संसद के कई सदस्यों की शिकायत के बाद रमेश बिधूड़ी का बयान दर्ज कराया जाएगा। बता दें कि संसद के विशेष सत्र के दौरान चंद्रयान-3 मिशन पर सदन में चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी।

**\* भाजपा सांसदों ने दानिश अली पर लगाए थे आरोप**

रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद काफी हंगामा हुआ और कई राजनीतिक पार्टियों के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ला को पत्र लिखकर बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया कि दानिश अली ने रमेश बिधूड़ी को उकसाया और वह बिधूड़ी के

संबोधन के दौरान बार-बार पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी रमेश बिधूड़ी के बयान की निंदा की लेकिन ये भी कहा कि दानिश अली ने ही उन्हें उकसाया था। लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ला ने उन्हें मिली शिकायतों को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति को भेज दिया था। विशेषाधिकार समिति की अध्यक्षता भाजपा सदस्य सुनील कुमार सिंह कर रहे हैं। हाल ही में रमेश बिधूड़ी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हर जनप्रतिनिधि का जनता के प्रति दायित्व बनता है। सदन के किसी खास सदस्य के प्रति लगातार कमेंट करते रहना और पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि अगर उन्हें (दानिश अली) मेरी बात बुरी लगी तो वो मुझे फोन करते, मामला तुरंत समाप्त हो जाता लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बदले उन्होंने केजरीवाल जैसी रणनीति अपनाई। उन्होंने मेरे मुद्दे पर राजनीति की। दानिश अली और ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम टुष्टीकरण कर रहे हैं।

## आपराधिकता जुड़ी होगी तो सांसदों को मिली मुकदमे से छूट पर विचार करेंगे, कोर्ट की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को एक अहम टिप्पणी में कहा है कि अगर मामले में आपराधिकता जुड़ी है तो कानून निर्माताओं को मिली कानूनी छूट पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों-विधायकों को मुकदमे से छूट देने वाले 1998 के आदेश की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि 1998 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत सांसदों और विधायकों पर संसद और विधानसभाओं में भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्तत लेने जैसे मामलों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें इस बात पर विचार करना होगा कि अगर मामले में आपराधिकता जुड़ी



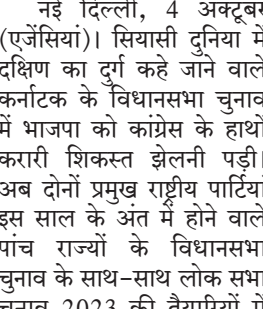
है तो क्या तब भी सांसदों-विधायकों को विशेषाधिकार का फायदा दिया जाए या नहीं। पीठ ने 1998 के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि यह माना कि आपराधिकता के बावजूद कानून निर्माताओं को छूट मिली हुई है। मुख्य न्यायाधीश के अलावा इस संविधान पीठ में जस्टिस एएस बोपड़ा, जस्टिस एम एम सुदेंद्रश, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। बीती 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नोट के बदले वोट मामले में 1998 के फैसले की समीक्षा के लिए संविधान पीठ का

गठन किया था। संविधान पीठ ने इस मामले पर आज सुनवाई की। बता दें कि ड्रामामो प्रमुख और पूर्व सीएम सोरेन, उनकी बहू सीता सोरेन समेत पार्टी के चार सांसदों पर आरोप लगा था कि 2012 में राज्यसभा चुनाव के दौरान एक विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए उन्होंने रिश्तत ली थी। इस पर सीबीआई ने सोरेन और उनकी पार्टी के सांसदों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस पर सीता सोरेन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर कहा कि संवैधानिक प्रावधान सांसदों को इन मामलों में मुकदमे से छूट देते हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले

को रद्द कर दिया था। **\* क्या है 1998 का फैसला**

उल्लेखनीय है कि साल 1998 में पांच जजों की संविधान पीठ ने पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में फैसला देते हुए कहा था कि सांसदों-विधायकों को संविधान के अनुच्छेद 105(2) और अनुच्छेद 194(2) के तहत आपराधिकता मामलों में छूट मिली हुई है, जिसके तहत सदन में पैसों के बदले सदन में भाषण देने और वोट देने के मामले में उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अनुच्छेद 105(2) कहता है कि संसद का कोई भी सदस्य सदन में किसी भी भाषण या वोट देने के लिए अदालत की कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अनुच्छेद 194 के तहत ऐसी ही सुविधा विधानसभा के लिए दी गई है।

## कर्नाटक में भी निकला जाति का जिन्न मोइली की मांग-सिद्धारमैया जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करें



नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। सिविसी दुनिया में दक्षिण का दुर्ग कहे जाने वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। अब दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां इस साल के अंत में होने वाले पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ-साथ लोक सभा चुनाव 2023 की तैयारियों में जुटी हैं। राजनीतिक रणनीति बनाने पर मंथन के अलावा तमाम दल वोट बैंक और जातियों को साधने की कवायद कर रहे हैं।

**\* पांच साल पहले बनी रिपोर्ट**

उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण में भी जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों पर बात शुरू हो गई है। कांग्रेस के कदावर नेता और पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से मांग की है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े और लगभग पांच साल पहले तैयार हुई रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। **\* सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल में तैयार हुई रिपोर्ट**

वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री मोइली ने कहा कि सिद्धारमैया के पिछले कार्यकाल (2013-18) के

उन्होंने कहा कि 2018 के बाद भी कांग्रेस और जनता दल सेकुलर (जेडीएस) की सरकार में जब एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे तो उनके पास भी कथाराज आयोग की रिपोर्ट जमा थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की सरकार गिरने के बाद जब भाजपा के बीएस येदियुरप्पा और उनके बाद बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री बने, तब भी जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सरकार के पास थी। कथाराज आयोग की रिपोर्ट पिछले पांच साल में जारी नहीं होने के कारण पर मोइली ने कहा, इसका केवल एक ही मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस जाति आधारित जनगणना कराना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि दनों दलों ने कथाराज कमीशन की रिपोर्ट रिलीज नहीं कराई। मोइली ने करीब 30 साल पुराने वाक्ये का जिक्र करते हुए कहा, 1992 में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने चित्रप्पा रेड्डी आयोग की रिपोर्ट जारी की थी।















## जब मोबाइल पर आया एक मैसेज तो मच गया बवाल

**पुलिस ने बुलाकर लिखी एफआईआर, 20 महीने से काट रहा था थाने की चक्कर** ग्रेटर नोएडा, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की दनकौर पुलिस का एक कारनामा सामने आया है। करीब 20 महीना पहले चोरी हुई एक बाइक की रिपोर्ट पुलिस ने अब दर्ज की है। युवक बाइक चोरी के बाद थाने के कई चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाइक चोरी होने के करीब 2 महीने बाद चालान हुआ तो युवक ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की और साथ ही आलाधिकारियों को सूचित किया। मामले की जांच हुई और 20 महीने बाद 30 सितंबर को बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल, फरवरी 2022 में दनकौर क्षेत्र स्थित खेरली नहर के पास से रोहित नाम के एक सेल्समैन की बाइक चोरी हो गई थी। उस समय पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। अब चोरी हुई बाइक के चालान का मैसेज पोर्टल के मोबाइल पर आया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है।

## लोकसभा चुनाव 2024: ओबीसी वोटों पर सबकी नजर

लखनऊ, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी में जातीय जनगणना की मांग को लेकर कांग्रेस ने अब जिलों का रुख कर दिया है। मंडल स्तर पर सम्मेलनों के बाद जिलों-जिलों में बैठके आयोजित करने की शुरुआत हो गई है। इसमें जातीय जनगणना की जरूरत लोगों को बताई जा रही है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि आखिर सरकार जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है? जिला स्तर पर सम्मेलन के बाद इसे ब्लॉक और न्याय पंचायतों तक भी ले जाया जाएगा। जातीय जनगणना का मसला अब तक कांग्रेस ने इतने पुरजोर तरीके से नहीं उठाया था। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की

### ‘मुस्लिम महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीन

### मेरी मां भी ऐसे ही मरी’ शिवानी बन शबाना ने सुनाई कहानी

बरेली, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। मुस्लिम धर्म में महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। मेरी मां भी बच्चे पैदा करते-करते मर गईं। हिंदू धर्म में खुली हवा में सांस लेने की आजादी है। मैं शिव भक्त हूं... ’ ये बातें शबाना से शिवानी बनी महिला ने कही हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली शिवानी ने अपने हिंदू प्रेमी से शादी की है और वो हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक रहना पसंद करती हैं। शिवानी ने बुर्का, हिजाब, तीन तलाक, हलाला और बहु विवाह को कुप्रथा बताया। बरेली में शिवानी ने मंगलवार को हिंदू धर्म अपना लिया। फरीदपुर की रहने वाली 21 साल की शबाना अब शिवानी बन गई है और उसने अरविंद के साथ हिंदू रीति रिवाज

## पश्चिम यूपी में मौसम ने ली करवट सुबह छाया घना कोहरा

लखनऊ, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। कानपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में जहां सुबह से तेज धूप निकली है वहीं पश्चिमी यूपी के बदायूं, शाहजहांपुर में बदल डेरा डाले हुए हैं। सुबह को मौसम कोहरा छाया था। वाहनों को लाइट जलाकर निकलाना पड़ा। वहीं अन्य हिस्सों में धूप और बादलों की लुकाछिपी जारी है। रुहेलखंड समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून की विदाई के साथ कोहरे छाने लगा है। बुधवार सुबह गंगा, रामगंगा समेत नमी वाले क्षेत्रों में मौसम का परिदृश्य बदला नजर आया। कोहरे की तरह की धुंध छाई रही। सघनता की वजह से सुबह साढ़े सात बजे वाहनों की लाइट जलाकर सफर तय करना पड़ा। यहीस्थिति गंगा, रामगंगा क्षेत्र में शाम थी वायुमंडल की नमी भी 58 प्रतिशत दर्ज हुई। राज्य कृषि मौसम केंद्र के प्रभारी व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डा। अतुल सिंह ने बदले परिदृश्य को मानसून विदाई का संकेत बताया है। बदायूं में भी मौसम का मिजाज बदल गया है।

## लैंड फॉर जॉब घोटाला: लालू-तेजस्वी-राबड़ी को जमानत

पटना, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सांसद मीसा भारती को जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अदालत ने राबड़ी, लालू और तेजस्वी यादव समेत 15 आरोपितों को 50000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसके अलावा अन्य दो आरोपियों ने बेल के लिए आवेदन नहीं दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष सुनवाई हुई। नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार के पूर्व सीएम और राजद प्रमुख लालू यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इनके साथ राज्यसभा सांसद मिसा भारती और मनोज झा भी कोर्ट पहुंचे। सुनवाई से पहले मीडिया से बातचीत के

### लालू बोले सभी को मिलेगा लाभ

मीडिया से बातचीत के दौरान लालू ने कहा कि बिहार में जातीय गणना हमलोगों ने करा दी है, अब यह पूरे देश में होना चाहिए। लालू ने कहा कि जातीय गणना से पूरे देश में गरीबों और दलितों को लाभ होगा। इससे सभी को सही हक मिलेगा, अभी तक किसी को वाजिब हक नहीं मिलता था, अब जातीय गणना को लेकर आगे भी काम करना है। वहीं, जब मीडिया द्वारा पूछा गया कि अब आगे की क्या प्लानिंग है? क्या आरक्षण के दायरे को 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा? इसपर जवाब देते हुए लालू ने कहा कि संख्या के अनुरूप आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाएगा।

दौरान लालू यादव ने कहा कि सुनवाई होती रहती है और वह इससे डरते नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। बता दें कि 22 सितंबर को दिल्ली की एक अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य आरोपियों को समन जारी किया था। सीबीआई ने हाल ही में कथित इस घोटाला



### लालू बोले- भाजपा की हकमारी पकड़ में आई

इसके अलावा, लालू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा को भी घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लंबे समय तक लोगों का हक मारा है, अब उसकी हकमारी पकड़ में आई है। गौरतलब है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। इसके लेकर लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना से दिल्ली पहुंच गए हैं।

अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर जमीन लेकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। वहीं, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद राजनीतिक सरगमीं तेज हो गई है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच, लालू यादव आज

### मुजफ्फरपुर में महिला की गोली मारकर हत्या

मुजफ्फरपुर, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा अली मिर्जा रोड में 4 अक्टूबर की रात एक महिला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह फिजियोथेरेपी करारक लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में बाइक से पहुंचे बदमाशों ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दे दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हत्या का कारण पता नहीं चला है। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद किया है। इस मामले में टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित ने कहा मामले की जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बाइक सवार दो लोगों ने अंजाम दिया है।

## यूपी के इस चर्चित आईएस ने दिया इस्तीफा, फरवरी से चल रहे थे सरपेंड



लखनऊ, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। 2011 बैच के आईएसएस अधिकारी अभिषेक सिंह ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। वे फरवरी 2023 से ही निर्लंबित चल रहे थे। 2011 बैच के आईएसएस अफसर उस वक्त सुखियों में आए थे जब उन्हें गुजरात चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक बनाया गया था और उन्होंने सरकारी गाड़ी के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उनकी पत्नी दुर्गाशक्ति नामपाल भी 2010 की आईएसएस अधिकारी हैं और मौजूदा समय में बांदा जिले की डीएम हैं। मूलतः जौनपुर जिले के रहने वाले अभिषेक सिंह ने 2011 में यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद 2013 में पहली



मेडिकल लीव पर चले जाने के बाद उन्हें 2020 में उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया गया था। मिल रही जानकारी के मुताबिक अभिषेक सिंह अपनी नई पारी सियासत से शुरू कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों ही उन्होंने जौनपुर में भव्य गणेशोत्सव का आयोजन करवाया था, जिसमें कुछ बॉलीवुड के एक्टर भी शामिल हुए थे। उनके इस आयोजन को चुनाव लड़ने से जोड़ कर देखा गया था। कहा जा रहा है कि अभिषेक सिंह 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। अभिषेक सिंह बॉलीवुड की कुछ फिल्मों और एल्बम में एक्टिंग भी कर चुके हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं।

## विधान परिषद-विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच सीबीआई ही करेगी एचसी ने स्वारिज की रिव्यू पिटीशन

प्रयागराज, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने विधान परिषद और विधानसभा में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच को लेकर विधान परिषद की तरफ से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट में जस्टिस एआर मसूदी और जस्टिस ओपी शुक्ला की डबल बेंच ने सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखते हुए रिव्यू पिटीशन खारिज की है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर 29 सितंबर को यूपी विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच शुरू कर दी गई थी, लेकिन विधान परिषद की तरफ से सीबीआई जांच के आदेश को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई, जिसे हाई कोर्ट के डबल बेंच में जस्टिस ए और मसूदी और ओपी शुक्ला की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। माना जा रहा है कि सीबीआई की एंटी



करप्शन ब्रांच जल्द विधानसभा और विधान परिषद के सचिवालय में हुई भर्ती को लेकर दस्तावेज जुटाने के लिए पृष्ठताछ का दौर शुरू करेगी।

### क्या था पूरा मामला?

दरअसल, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई है कि विधानसभा और विधान परिषद में तृतीय श्रेणी के पदों के लिए भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए ही कराई जाए। विचारों में मांग की गई की विधान परिषद सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा

### अधिकारी और अपर निजी सचिव

सहित 11 कैडर के लिए 99 पदों पर 17 जुलाई 2020 और 27 सितंबर 2020 के विज्ञापनों के बाद भर्ती की गई उनको निरस्त किया जाए। आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। अफसर और नेताओं की मिली भगत से उनके ही परिवार वालों को नौकरी दी गई। परीक्षा वाले दिन गोरखपुर में पेपर लीक हुआ। 7 दिसंबर 2020 को विधानसभा सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 और समीक्षा अधिकारी के 53 पदों समेत कुल 87

## 4 हजार रुपये की घूस लेते महिला लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार

कानपुर, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक महिला लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के घाटमपुर इलाके में एक महिला लेखपाल किसान की जमीन का चिन्हाकन करने के लिए 4 हजार रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुई। एंटी करप्शन टीम ने महिला लेखपाल अंजली यादव को उनके परिचित दुकानदार के साथ घुस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने लेखपाल और उनके परिचित दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जबकि डीएम ने महिला लेखपाल को सरपेंड कर दिया है।

### क्या है पूरा मामला?

कानपुर के घाटमपुर के रहने वाले राजेश कुमार की जमीन थी, जिसमें उनके दो भाई और शामिल थे। राजेश कुमार ने अपनी जमीन को अपने नाम करके अपने हिस्से की जमीन का चिन्हाकन करने के लिए लेखपाल अंजली यादव से अपील की। आरोप है कि महिला लेखपाल ने राजेश कुमार से 5 हजार रुपये की घूस की मांग कर ली और दोनों के बीच 4 हजार



रुपये पर मामला तय हुआ। इसके बाद उन्होंने पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एंटी करप्शन टीम को भी इसकी सूचना दे दी। राजेश ने घूस देने के लिए महिला लेखपाल से बात की तो उन्होंने एक दुकानदार शिवराज सिंह की दुकान पर पैसा लेने के लिए बुलाया। राजेश पैसा लेकर पहुंचे तो दोनों ने घूस को पैसा ले लिया, लेकिन इसी दौरान एंटी करप्शन टीम ने महिला लेखपाल और उनके दुकानदार को पैसा लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दोनों को हनुमान बिहार पुलिस को सौंप दिया गया है। थानेदार उदय प्रताप ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर लिखकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

## बिहार जाति जनगणना: 'जितनी भागीदारी

### उतनी हिस्सेदारी', तो क्या अब फिर होगा मंत्रिमंडल विस्तार?



पटना, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। बिहार जाति जनगणना के बाद से ही प्रदेश में 'जितनी भागीदारी, उतनी हिस्सेदारी' को लेकर नई बहस छिड़ गई है। आबादी के एतवार से आरक्षण और हिस्सेदारी पर चर्चा हो रही है। अलग-अलग समुदायों के नेता अपनी-अपनी जातियों के लिए प्रतिनिधित्व की गलातल कर रहे हैं। सियासी गलियारों में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद देने की चर्चा कर रहे हैं। धीरे-धीरे यह मांग सियासी रूप लेते हुआ भी नजर आने वाला है। बिहार सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के बाद अलग ही सियासी समीकरण बनने लगे हैं। जाति आधारित गणनों के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग की

सियासत मजबूत होने का दावा होता रहा है, वहीं 2.87 फीसदी आबादी वाली कुर्मी जाति से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो फिर क्यों नहीं नीतीश को सीएम पद से हटाकर तेजस्वी को सीएम बना दिया जाए और मुस्लिम चेहरा को डिप्टी सीएम बनाया जाए। प्रदेश के सियासी गलियारों में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व कर रहे लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद देने की चर्चा कर रहे हैं। धीरे-धीरे यह मांग सियासी रूप लेते हुआ भी नजर आने वाला है। बिहार सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के बाद अलग ही सियासी समीकरण बनने लगे हैं। जाति आधारित गणनों के मुताबिक अति पिछड़ा वर्ग की

### एनएच-27 पर भीषण सड़क हादसा

**गुरुग्राम से बिहार जा रही बस और ट्रक की टक्कर, 2 यात्रियों की मौत, 9 घायल** अयोध्या, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। लखनऊ-अयोध्या एनएच-27 पर बुधवार को हुए भीषण सड़क दुर्घटना में बिहार के दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 9 यात्री घायल हो गए। सात यात्रियों को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज व दो यात्रियों को अयोध्या के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम से यात्रियों से भरी एक बस बिहार के मधुबनी जा रही थी और जैसे ही भोर में अयोध्या पहुंची तभी किन्हीं कारणों से बस कोतवाली नगर के नाका ओवर ब्रिज पर रुक गई और पीछे से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। मरने वाले यात्री बिहार के मधुबनी व सुपौल के रहने वाले हैं।

### वाराणसी में दर्दनाक हादसा कार और ट्रक की भिड़ंत में आठ लोगों की मौत



वाराणसी, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। वाराणसी से एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। फूलपुर थाना के करखियांव में कार और ट्रक की भिड़ंत में आठ लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतकों की पहचान पीलीभीत निवासी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सभी वाराणसी दर्शन-पूजन के लिए आए थे और वापस घर लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। एक्स पर सीएम के ऑफिसियल अकाउंट से पोस्ट में लिखा- 'मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जनपद वाराणसी में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुःख प्रकट किया है। महाराज जी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देशित किया है। महाराज जी ने बाबा विश्वनाथ से दिवंगत आत्माओं की शान्ति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।

### 35 साल की महिला को पत्नी की तरह रखने

### लगा 75 साल का तॉत्रिक, फिर हुआ ये अंजाम

गोंडा, 4 अक्टूबर (एजेंसियाँ)। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 30 सितंबर को महिला की अधजली लाश मिली थी। इस मामले की जब पुलिस ने जांच-पड़ताल की तो पूरी घटना का खुलासा हो गया। दरअसल, 35 साल की महिला 75 साल के तॉत्रिक के साथ पत्नी की तरह रहने लगी थी। महिला ने तॉत्रिक की किसी बात को मानने से इनकार कर दिया था। इसी को लेकर तॉत्रिक ने महिला की हत्या कर लाश जला दी थी। जानकारी के अनुसार, बीते 30 सितंबर को गोंडा के खोंडार थाना क्षेत्र के कुआने जंगलों में महिला का शव मिला था। पुलिस ने शव मिलने के बाद तपतीश शुरू की और उसकी शिनाख्त कराई तो उसकी पहचान सिद्धार्थनगर निवासी मीना के रूप में हुई। पुलिस ने इस मामले में महिला के परिजनों की शिकायत पर आरोपी तॉत्रिक भगवानदीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।





# महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फिर बनेंगे नए समीकरण

मुंबई, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। अजित पवार की कैबिनेट मीटिंग में गैर-मौजूदगी से महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से किसी नए समीकरण की ओर इशारा करते दिखाई पड़ने लगे हैं। अपने समय और काम के पाबंद अजित पवार के बीते दिन मंत्रिमंडल की बैठक में गैर-मौजूदगी ने कई सवाल खड़े किए हैं। अपने राजनीतिक और मंत्रिपद के कार्यकाल में शायद ही अजित पवार मुंबई में होने के बाद भी गैरमौजूद रहे हों। बीते दिन कैबिनेट के मीटिंग में सबसे पहली चर्चा नांदेड के सरकारी अस्पताल में 24 मौतों पर हुई जो एक ही दिन में दर्ज की गई थी। इन मौतों से सरकारी अस्पताल की बदईतजामी फिर एक बार सामने आई है।

**तीन सदस्यीय टीम का गठन** गौरतलब है कि यह अस्पताल मेडिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है और इस विभाग के मंत्री हसन मुशरिफ हैं और हसन मुशरिफ अजित पवार गुट के हैं। दवाईया उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की है जिसके मंत्री तानाजी



सावंत हैं और ये एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं। मौत की वजह जरूरी दवाइयों का अभाव है या फिर डॉक्टर, नर्स का मौजूद न होना या और कुछ और। इस सबकी जांच के लिए सरकार तीन सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जल्द ही रिपोर्ट पेश करने के आदेशे मुख्यमंत्री ने दिए है।

**उठाए थे मुख्यमंत्री एकनाथ पर सवाल**

कुछ महोने पहले जब ठाणे के अस्पताल में एक ही दिन में 18 मरीजों की मौत का मामला सामने आया था, तब राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने मुख्यमंत्री एकनाथ पर



सवाल उठाए थे। सूत्र बताते हैं कि अजित पवार ने कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से पूछा था कि आपके ठाणे शहर के अस्पताल में क्या चल रहा है? इस एकनाथ शिंदे ने हंसकर टाल दिया था। उस वक़्त मौजूद देवेंद्र फडणवीस ने भी बीच-बचाव कर बहस को दूसरी दिशा में मोड़ दिया था, लेकिन इस विवाद का असर यह हुआ कि अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। आइए नजर डालें उन घटनाक्रम पर जिस कारण अजित पवार और एकनाथ शिन्दे में दूरियां बढ़ती नजर आईं।

**कई मौकों पर साथ नहीं गए अजित पवार**

जानकारी दें कि जब जालना में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल से मिलने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गए तो वहां अजित पवार साथ नहीं गए। फिर जब अमित शाह गणपति दर्शन के लिए मुंबई आए, उस वक़्त भी अजित, अमित शाह से मिलने नहीं पहुंचे। वहीं, जेपी नड्डा मुंबई आए तब भी अजित पवार पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। अजित पवार के पास वित्त मंत्रालय होने की वजह से वह सभी विभागों के बड़े प्रोजेक्टों की फाइल देखने लगे, जो एकनाथ शिंदे को नागवार गुजरी। **बढ़ती जा रही है दूरियां** उल्लेखनीय है कि अजित पवार की प्रशासन पर पकड़ है। कई सालों तक मंत्री बने रहने और कई मंत्रालयों में काम करने का उन्हें गाढ़ा अनुभव है। कहा जाता है कि मौजूदा सरकार में भले ही मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे हों

लेकिन सरकार के अहम निर्णय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रजामंदी के पूरे नहीं होते। अब जबकि अजित पवार भी सरकार का हिस्सा है और वित्त मंत्रालय उनके पास होने की वजह से हर एक विभाग में अपना हस्तक्षेप रखते हैं। ऐसे में दूरियां तो बढ़ेंगी ही। सूत्रों की माने तो मंत्रीमंडल का तीसरे विस्तार में कुछ ही दिनों में हो सकता है क्योंकि अभी 14 मंत्री पद बाकी बचे हुए हैं, जिसमें से अजित पवार गुट के एक कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति अपना कुनबा सम्भालने के लिए एकनाथ शिंदे गुट को ज्यादा मंत्री पद की जरूरत है। वहीं बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं जिन्हें मंत्री पद की आस है इसलिए अब और मंत्री पद मांगा गया है, साथ ही गार्जियन मंत्री पद के लिए भी मांगा गया जिला शिंदे व फडनवीस के देने से इनकार करने की खबरें भी राजनीतिक गलियारों में चर्चित हैं।

**अजित पवार साथ नहीं आए दिल्ली**

बीते दिन एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, लेकिन अजित पवार साथ नहीं आए। इसका कारण बताया गया उनकी तबियत ठीक नहीं है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार की तबियत ठीक नहीं इसीलिए वे मंत्री मंडल की बैठक में नहीं आए उनकी गैर मौजूदगी का कोई और मतलब निकलने की जरूरत नहीं है। अजित पवार ने हाल ही में बायमती दौरे पर कहा था कि आज उनके पास वित्त मंत्री पद है, वे सरकार में हैं कल होंगे या नहीं पता, कल किसी ने नहीं देखा है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो अजित पवार की नाराजगी सरकार में शामिल होने के दिनों से ही दिखाई दे रही थी जो अब और गहरी होती जा रही है इसलिए अपने फैसले से हमेशा सभी को चौका देने वाले अजित पवार कोई और चौकाने वाला फैसला ले तो आश्चर्य नहीं होगा।



मुरैना, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के छोटे से गांव के रहने वाले आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा ऐसे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा हैं जो मोहब्बत में उलझ कर समय और करियर बर्बाद कर लेते हैं। आईपीएस मनोज शर्मा ने प्यार की खातिर सारी विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़कर यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर लिया। इन आईपीएस अधिकारी से प्रभावित होकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उनसे मिलने की इच्छा तक जाहिर की है। आईपीएस अधिकारी मनोज शर्मा को लेकर लेखक अनुराग पाठक ने 'दवेल्थ फेल' पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन सभी बातों का उल्लेख किया गया है जो मनोज शर्मा ने सहा है। मुरैना के रहने वाले मनोज शर्मा ने काफी गरीबी देखी। उन्होंने कक्षा

आठवीं, दसवीं में तीसरा स्थान हासिल कर पॉसिंग मार्क्स अर्जित किए। इसके बाद जब उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी तो फेल हो गए। इस दौरान उन्हें अपनी क्लासमेट श्रद्धा से प्रेम हो गया। जब 12वीं फेल हो गए तो उन्होंने मायूस होने की वजह अपने हीसले को और बुलंद कर दिया। एक बार मनोज शर्मा ने श्रद्धा से बातों ही बातों में कह दिया, यदि वह हां, कर दे तो दुनिया भी पलट सकते हैं। मनोज शर्मा ने केवल कहा ही नहीं बल्कि कर दिखाया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में 121वीं रैंक हासिल कर आईपीएस कैडर में उपस्थिति दर्ज करा दी। उन्होंने क्लासमेट श्रद्धा से ही विवाह किया और वर्तमान में आईपीएस अधिकारी की पत्नी भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी है।

## 'चुनाव लड़ने पर मैं नहीं, मेरी पार्टी बात करेगी'

बीजेपी से नाराजगी की अफवाहों के बीच क्या बोलों उमा भारती?



भोपाल, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। पिछले दिनों पूर्व सीएम उमा भारती ने प्रदेश की राजनीति में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उछाल दिया था, जिससे बीजेपी की टेशन बढ़ गई थी। इसके बाद पार्टी संगठन से लगातार नाराजगी की चर्चा के बीच बीजेपी की फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम भारती इन दिनों लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को जनता

के सामने रख रही हैं। उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि, 'मैं जो ट्वीट करती हूं उससे अधिकतम लोगों से मेरा संपर्क, कई खबरों की पुष्टि और कई खबरों का खंडन हो जाता है।

**'चुनाव लड़ने पर पार्टी लेगी फैसला'**

वहीं अपने दूसरे ट्वीट में उमा भारती ने कहा कि, '2024 का चुनाव लड़ने की बात तो मैंने 2019 में कही थी, विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा पूर्णतः निराधार थी, अब मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने पर मैं नहीं, मेरी पार्टी बात करेगी।' वहीं अपने तीसरे ट्वीट में उमा भारती ने कहा कि, 'भैया दूज तक जो कि 15 नवंबर को है, चार धाम के लगभग सब कपाट बंद हो जाते हैं। मैं चार-पांच दिन पहले ही हिमालय छोड़ देती हूं। क्योंकि जो

व्यक्ति कपाट बंद होने के समय वहां रहता है उसे कपाट खुलते समय भी वहां रहना चाहिए, यही नीति एवं परंपरा है। कपाट खुलते समय कई बार वहां पहुंचना मुश्किल हो जाता है।'

**'मैं बेहद खुश हूं कि'**

बता दें कि, अपने आखिरी ट्वीट में उमा भारती ने कहा, 'मैं बेहद खुश हूं जिंदगी की हर घड़ी सार्थक है एवं खुशियों से भरपूर है। मेरी खुशियां तो इसी से निकल रही हैं कि मैं आपके काम आती हूं।' वहीं उमा भारती ने कहा था कि, 'हमारी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कुछ केंद्रीय मंत्रियों एवं सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है, इस निर्णय का अभिनंदन। यह सभी नाम अपने-अपने क्षेत्र में ऐसी लहर पैदा करेंगे जिससे पूरा प्रदेश विधानसभा चुनाव में लाभान्वित होगा।



नैनीताल, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। कर्बेट टाइगर रिजर्व में लंबे समय से अपनी सेवा दे रही गोमती हथिनी और ब्रांडी कुत्ता आज रिटायर हो गए। बुधवार को विदाई देते हुए उन्हें सेवानिवृत्त किया गया। कर्बेट प्रशासन ने आमडंडा गेट पर दोनों के लिए भव्य विदाई समारोह आयोजित किया। गोमती को 40 साल पहले आसाम से लाया गया था। गोमती हथिनी ने कई महत्वपूर्ण अभियानों में अपना योगदान दिया। 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद अब गोमती को एनटीसीए के मानक के अनुरूप सेवानिवृत्त कर दिया गया। वहीं, स्नीफर डॉग ब्रांडी को भी सेवानिवृत्त किया गया। ब्रांडी ने भी कई महत्वपूर्ण अभियानों में अपनी भूमिका निभाई है।

## एसवाईएल नहर विवाद मामला

एससी ने पंजाब सरकार को क्यों कहा- हमें मजबूर ना करें

चंडीगढ़, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। सतलुज यमुना लिंक (एसबीएल) नहर विवाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि इस मामले में राजनीति ना करें। कोर्ट ने आगे कहा है कि हमें मजबूर ना करें कि हम इस मामले में कोई सख्त आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि पंजाब में एसवाईएल नहर बनने की प्रक्रिया को लेकर सर्वे शुरू किया जाए। कोर्ट ने पंजाब सरकार को केंद्र सरकार के सर्वे करने की प्रक्रिया में मदद करने के लिए कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार दोनों राज्यों को बीच में इस विवाद का हल निकालने के लिए पहल करे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हरियाणा में एसवाईएल नहर बनाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, लिहाजा पंजाब भी इस समस्या का हल निकालने की दिशा में काम करे। कोर्ट ने कहा

कि हम लंबे समय से चल रहे इस विवाद का हल निकालने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पंजाब सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी कि पंजाब में एसवाईएल नहर के निर्माण के मौजूदा हालात कैसे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे हफ्ते में होगी।

**क्या है विवाद**

1966 में पंजाब के अलग होकर हरियाणा का गठन होने के बाद से ही सतलुज-यमुना लिंक नहर का विवाद चला आ रहा है। अप्रैल 1982 में नहर का निर्माण शुरू हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव में इसकी शुरुआत की थी। इसके तहत 214 किमी लंबी नहर बनाई जानी है। इसका 122 किमी हिस्सा पंजाब में और बाकी 92 किमी हिस्सा हरियाणा में बनना है। लेकिन इसे लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद है। इस नहर का पानी दिल्ली तक भी आना है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार है।

## जज की हत्यारी महिला डॉक्टर को हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत समय पूर्व रिहाई की मांग पर होगा विचार

चंडीगढ़, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एडीजे विजय सिंह की हत्या की दोषी डॉ। रवदीप कौर को समय पूर्व रिहाई की मांग पर पंजाब सरकार को विचार करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आखिरी सांस तक कैद की सजा पर भी अपने फैसले में सवाल उठाया है और समय पूर्व रिहाई की मांग पर फैसला होने तक याची को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। 13 अक्टूबर 2005 की रात पंडिशनल सेशन जज विजय सिंह की पटियाला में हत्या कर दी गई थी।

2012 में रवदीप कौर व एक सुपारी किलर मंजीत सिंह को चंडीगढ़ की ट्रायल कोर्ट ने हत्या की दोषी मान उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिसके खिलाफ अपील हाईकोर्ट में लंबित है। एफआईआर के अनुसार रवदीप कौर पटियाला



में प्रसूति अस्पताल चलाती थी और विजय सिंह चंडीगढ़ लेबर कोर्ट में जज थे। दोनों उस समय संबंध में थे। विजय सिंह ने पत्नी से तलाक लेकर याची से शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसी के चलते सुपारी किलर मंजीत सिंह से विजय सिंह की हत्या करवा दी गई। याची ने कहा कि 2011 की नीति के अनुसार महिला दोषी को आठ साल के वास्तविक और छूट के साथ 12 साल के कारावास के बाद उसकी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि

रवदीप कौर 17 साल असल और छूट के साथ 22 साल और सात महीने की सजा काट चुकी है, जो न्यूनतम निर्धारित अधि से कहीं अधिक है। सरकार का तर्क था कि याची को उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा दी गई है, ऐसे में समय पूर्व रिहाई पर विचार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को किसी कैदी को अंतिम सांस तक की सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। सरकार ने बताया कि याची 2014

## कंपनी पार्टनर को खुश करने के लिए रखी न्यूड पार्टी

कपड़े उतारकर हो रहा था डांस, पुलिस ने मारी रेड

नागपुर, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। नागपुर में एक चौकाने वाली घटना सामने आई है जहां एक बिजनेसमैन ने पार्टी में लड़कियों को हाफ न्यूड कर डांस कराया। नागपुर के पास पचगांव में रिसॉर्ट में डांस पार्टी चल रही थी। महाराष्ट्र पुलिस ने डांस पार्टी पर छापा मारा और 37 लोगों को गिरफ्तार किया। ये जानकारी महाराष्ट्र पुलिस ने दी। पुलिस ने बताया कि कई लोग हाफ न्यूड पाए गए। वो पार्टी में अश्लील डांस कर रहे थे। पुलिस ने इनके

खिलाफ आईपीसी और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि रविवार देर रात छापेमारी की गई। 13 डांसर्स सहित 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये पार्टी कोटनफाका का कारोबार करने वाली एक कंपनी द्वारा 75,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वालों के लिए प्रोत्साहन के रूप में आयोजित किया गया था। रिसॉर्ट का मालिक गिरफ्तार इसकी जानकारी मिलते ही नागपुर पुलिस और लोकल क्राइम शखेल ने उस

रिसॉर्ट पर छापा मारा जहां पार्टी चल रही थी। पुलिस ने मौके से पार्टी में शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया है। रिसॉर्ट के मालिक और मैनेजर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि नागपुर के कुही थाना क्षेत्र के पचगांव स्थित सिल्वरी लेक फार्म केरने वालों के लिए प्रोत्साहन के रूप में आयोजित किया गया था। रिसॉर्ट का मालिक गिरफ्तार इसकी जानकारी मिलते ही नागपुर पुलिस और रिसॉर्ट पर छापा मारा। रिसॉर्ट में पुलिस की छापेमारी से पार्टी में

आए लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोगों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने जव्त किए 49 लाख रुपए रिसॉर्ट में न्यूड पार्टी की खबर सुनकर नागपुर के लोग हैरान हैं। नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रिसॉर्ट में लड़कियां बेहद महंगे कपड़े पहनकर डांस कर रही हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर वहां मौजूद लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने मौके से 49 लाख रुपये, विदेशी शराब और पांच कारें भी जव्त की हैं।





# असम सरकार के मॉडल की देशव्यापी जरूरत

**गुरुवार, 5 अक्टूबर - 2023**

## जाति आधारित जनगणना

जाति के आधार पर जनगणना की मांग वर्षों पुरानी है, इसके बाद भी यह मांग राष्ट्रीय स्तर पर आज भी बाट जोह रहा है। यहां तक कि अब तक इस मांग पर एक कदम भी नहीं बढ़ाया गया है। ऐसे माहौल में भी बिहार ने बाजी मार ली है। वहां की जनता दल (यू.) और राष्ट्रीय जनता दल की मौजूदा सरकार ने गांधी जयंती के दिन जातीय जनगणना के आंकड़े को जारी कर दिया। इस आंकड़े के मुताबिक बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी तिरसठ फीसद है। अनुसूचित जातियों की संख्या 19.65 फीसद और अनुसूचित जनजाति की 1.68 फीसद है। सामान्य वर्ग में आने वाली जातियों के लोगों की तादाद 15.52 फीसद है। धार्मिक आधार पर देखें तो कुल हिंदू आबादी 81.9 फीसद और मुसलिम 17.7 फीसद हैं। यानी जाति आधारित जनगणना के बाद राज्य में अलग-अलग जातियों और धर्मों के लोगों की संख्या के बारे में अब तस्वीर साफ हो गई है। राज्य सरकार की दलील है कि इसके जरिए सभी जातियों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी मिल गई है और इसी के आधार पर अब सभी सामाजिक वर्गों के विकास और उत्थान के लिए सरकार कदम उठाएगी। सरकार के दावे पर विश्वास किया जाए तो पाएंगे कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़े आने के बाद सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में भागीदारी का सवाल हल करने और जरूरतमंद तबकों की स्थिति में सुधार के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही यह देखने वाली बात होगी कि इसका उपयोग विकास और उत्थान में कितना होगा और कितना इसका इस्तेमाल राजनीतिक मुद्दे के तौर पर किया जाएगा। ऐसे में जो सवाल अक्सर उठाय़ा जाता रहा है कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को लक्षित सरकारी नीतियों में जिन तबकों की हिस्सेदारी तय की जाती है, उनके बीच के कुछ समर्थ स्तर उसका लाभ उठा लेते हैं और एक बड़ा तबका वंचित रह जाता है। खासकर पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी के संदर्भ में यह दावा किया जाता रहा है कि अब इस तबके की आबादी काफी ज्यादा हो गई है और इसके मुकाबले इन्हें मिलने वाला आरक्षण काफी कम है। इसके अलावा, जाति और वर्ग के आधार पर बनाई गई मौजूदा योजनाओं और कार्यक्रमों में कुछ खास सामाजिक समुदायों को आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनकी संख्या से संबंधित कोई अद्यतन पुछ्ता आंकड़े नहीं हैं। सवाल है कि इस मसले पर अब तक चलने वाली जटो जहद का कारण क्या सिर्फ यही रहा है कि इसके जरिए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में सभी तबकों को न्यायपूर्ण भागीदारी दिलाई जा सके! हो सकता है कि जाति और वर्ग के आधार पर बनने वाली नीतियों पर इसका असर दिखे। हालांकि यह अब बिहार सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा कि वह आबादी के अनुपात में सबकी भागीदारी और इसके साथ-साथ न्यायपूर्ण तरीके से बिना भेदभाव किए वंचित वर्गों के हित कैसे सुनिश्चित कर पाती है। बिहार में हुई इस कवायद का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक असर यह पड़ सकता है कि देश भर में जाति आधारित जनगणना की मांग जोर पकड़े और यह एक चुनावी मुद्दा भी बने। बहरहाल मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका है। इस पर उठाने पटना उच्च न्यायालय के इससे संबंधित फैसले के खिलाफ की गई अपील पर सुनवाई की स्वीकृति दे दी है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वक्त के साथ जाति के आधार पर पूर्वाग्रह-दुराग्रहों को कमजोर करना राजनीतिकों का दायित्व होना चाहिए। इसलिए बिहार में हुई जाति आधारित जनगणना को राजनीति का जरिया न बना कर इसे वंचित तबकों के लिए न्याय मुहैया कराने का ही आधार बनाया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सारी कवायद धरी की धरी रह जाएगी।

## योगी का सनातन संदेश

**डॉ दिलीप अग्निहोत्री**

विपक्ष का इंडी एलायंस के सदस्य हिन्दू धर्म पर हमला बोल रहे हैं, उसे धर्म नहीं धोखा बता रहे हैं, सनातन के उन्मूलन का एलान कर रहे हैं, मन्दिरों की मूर्तियों की प्रतिकृति के प्रतिकूल बयान दिए जा रहे हैं। जातिवाद और जातिगत वैमनस्य बढ़ाने वाले बयान दिए जा रहे हैं. इनमें से कोई भी दल विकास सद्भाव और समरसता की बात नहीं कर रहा है. क्योंकि ऐसा करने पर इनको भी अपना हिसाब दान पड़ेगा. इंडी एलायंस की अनेक पार्टियां सभी प्रदेशों में सत्तारूढ़ हैं. यूपीए सरकार में भी ये साझेदार रही हैं. इसलिए विकास पर मौन रहने में ही इन्हें अपनी भलाई दिखाई देती है. इसी प्रकार इमानदारी की बात भी नहीं होती. लेकिन नरेंद्र मोदी को हटाने का एकमात्र एजेंडा बनाया है. इसलिए एकादश राजनीति चल रही है. हिन्दू, सनातन,ठाकुर का कुंआ, हिन्दुओं के धार्मिक ग्रंथ आदि पर नकारात्मक बयान दिए जा रहे हैं. दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं. जिन्होंने बिना भेदभाव के अभूत पूर्व विकास करके दिखाया है। इसके साथ ही संस्कृतिक राष्ट्रवाद से प्रेरित बेमिसाल कार्य किए हैं. योगी श्री राम चरित मानस, हिन्दू और सनातन पर हमला बोलने वालों को उनकी औकात भी बता रहे हैं. जन्माष्टमी पर उन्होंने सनातन का अर्थ और भाव बताया था. यह मानव कल्याण का शाश्वत चिंतन है. उन्होंने कहा था कि जो सनातन रावण के अहंकार से नहीं मिटा, कंस के हुंकार से नहीं डिगा तथा बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से नहीं मिटा, वह ऐसे सत्ता के लोभी लोगों से क्या मिटेगा। इन्हें अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। रावण तथा हिरण्यकश्यप ने ईश्वर और सनातन धर्म की अवमानना करने का प्रयास किया था। कंस ने ईश्वरीय सत्ता को चुनौती दी थी, लेकिन वे सभी मिट गए। सनातन धर्म मानवता का धर्म है। दुनिया के सभी मत, मजहब



अशोक भाटिया

भारतीय राजनीति अपनी स्थापना के समय से ही इतने गूढ़ तरीके से उलझी रही है कि किसी भी सरकार के लिए समाज सुधार वाले निर्णय लेना आसान नहीं रहा है। जाति, मजहब की दीवारें अक्सर इन निर्णयों को ऐसी खाई में धकेल देती हैं कि उनके पुनर्जन्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लीग से हटकर चलना भारतीय राजनीति में एक चुनौती की तरह है जिससे राजनेता बचते आए हैं या ऐसा करके अपनी सत्ता बचाते आए हैं हालांकि इस स्थिति में साल 2014 के बाद से कुछ बदलाव की आहट गाहे-बगाहे कानों में गूंजती रही है। कुछ समय से इस मामले के केंद्र में हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का नाम असम बाल विवाह के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने यहां बाल विवाह करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। असम पुलिस ने इस बार बाल विवाह करने वाले 1000 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया है। सीमावर्ती राज्य असम में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा की खास पहल पर राज्य की पुलिस बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत बाल विवाह करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर हिमंता सरमा लिखते हैं कि बाल विवाह से खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई में असम पुलिस ने एक विशेष अभियान में 1000 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो

सुबह के शुरुआती घंटों में शुरू हुआ है। उनके अनुसार सामाजिक खतरे से संबंधित मामलों में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ने की संभावना है क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। 11 सितंबर को, सरमा ने असम समाज सुधार वाले निर्णय लेना आसान नहीं रहा है। जाति, मजहब की दीवारें अक्सर इन निर्णयों को ऐसी खाई में धकेल देती हैं कि उनके पुनर्जन्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती। लीग से हटकर चलना भारतीय राजनीति में एक चुनौती की तरह है जिससे राजनेता बचते आए हैं या ऐसा करके अपनी सत्ता बचाते आए हैं हालांकि इस स्थिति में साल 2014 के बाद से कुछ बदलाव की आहट गाहे-बगाहे कानों में गूंजती रही है। कुछ समय से इस मामले के केंद्र में हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का नाम असम बाल विवाह के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पुलिस ने यहां बाल विवाह करने वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। असम पुलिस ने इस बार बाल विवाह करने वाले 1000 लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया है। सीमावर्ती राज्य असम में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा की खास पहल पर राज्य की पुलिस बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत बाल विवाह करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर हिमंता सरमा लिखते हैं कि बाल विवाह से खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई में असम पुलिस ने एक विशेष अभियान में 1000 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो

नजर डालना बेहद अहम है। बीते साल मई माह में आई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएएस-5) की रिपोर्ट के अनुसार- असम में 20 से 24 वर्ष की उम्र की 31 प्रतिशत से ज्यादा ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले ही कर दी गई। वहीं, इस मामले में राष्ट्रीय औसत तकरीबन 23 प्रतिशत है। असम में 11.7 फीसदी लड़कियां कम उम्र में गर्भवती हो रही हैं। यह आंकड़े बड़ी संख्या में होने वाले बाल विवाह का जीते-जागते गवाह हैं। राज्य के सीमावर्ती जिले धुबड़ी में आंकड़ा और भी भयावह है जहां 50 फीसदी शादियां कम उम्र में हो रही हैं। ऐसे में लड़कियां कम उम्र में मां बनने को मजबूर हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार असम, देश में सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर वाला राज्य है, जबकि शिशु मृत्यु दर के मामले में यह तीसरे नंबर पर है। दरअसल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक, असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर है. बाल विवाह इसकी सबसे अहम वजह में गिनी जाती है क्योंकि राज्य में रजिस्टर्ड मैरिज में औसतन 31 फीसदी शादी के लिए प्रतिबंधित उम्र में रजिस्टर्ड हैं। वहां के डीजीपी के अनुसार अपने कम उम्र के बच्चों की शादी करने वाले परिवारों के सदस्यों के अलावा, पुलिस 'पुरोहितों' और 'काजियों' को गिरफ्तार कर रही है , जिन्होंने धार्मिक संस्थानों में इस तरह की शादी की रस्में निभाईं।उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां परिवार के निषिद्ध आयुवर्ग के हैं। असम सरकार यह कदम क्यों उठा रही है? इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर

# क्या जातीय गणना नीतीश सरकार के लिए भस्मासुर साबित होगी

**राज सक्सेना**

मोदी विरोध के चलते, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी के बरसों के प्रयास हिंदुत्व एकता के गुब्बारे में सुई चुभा ही दी। जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के तुरंत बाद पत्रकारों से मुखातिब नीतीश कुमार की ‘बाड़ी लॉवेज’ से स्पष्ट हो रहा था कि वे अपने इस कृत्य से ‘अति प्रसन्न’ हैं, बिना यह विचार किये कि उन्होंने न केवल बिहार बल्कि देश की राजनीति में तो कांटे बो ही दिए हैं अपितु स्वयं अपने राजनैतिक जीवन की मौत के वारंट पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस तरह के प्रयास की भूमिका बनाते समय नीतीश ने वही गलती दोहरा दी जिसे उनके और लालू-मुलायम आदि जातिवादी नेताओं के उकसाने पर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर अपने राजनैतिक जीवन को तो समाप्त कर ही लिया, देश को भी जातिवादी दलदल में धकेल दिया था। बिहार में जातीय गणना के आंकड़ों के प्रकाशित होते ही कई क्षेत्रीय दलों के साथ वह कांग्रेस भी अब जोर-शोर से जातीय गणना पर जोर देने लगी है जो अपने यूपीए शासन के समय जातीय गणना करवाने के बाद उसके आंकड़े जारी करने की हिम्मत ही नहीं कर सकी थी। कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार ने भी 2014-15 में जाति गणना तो कराई थी लेकिन उसका विवरण बताने से वह भी उसके दुष्परिणामों को सोचकर पल्टी मार गई थी। अब फिर से कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है लेकिन कोई नहीं जानता कि वह जाति गणना के आंकड़े जारी करने का इरादा रखती है या नहीं? राजस्थान में भी 2011 की जनगणना के समय तत्कालीन कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने जाति

आधारित गणना कराई थी लेकिन उसके आंकड़े उसने भी सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं की थी। जातियों की गणना करने की मांग करने वाले राजनैतिक दल इस बात पर जोर दे रहे थे कि, ‘जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो, उसकी सत्ता में उतनी ही भागीदारी भी हो’। बहुत सुनने में तो यह वाक्य देखते अच्छा लगता है लेकिन सामाजिक न्याय का ताकजा यही कहता है कि भागीदारा का आधार आर्थिक व सामाजिक स्थिति ही होनी चाहिए। सामाजिक न्याय के नाम पर सनातन समाज को जातीय रूप से विभाजित करने वाली वोट बैंक की राजनीति से जितना संभव हो सके, उतना बचा जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछड़ी कहीं जाने वाली कई जातियां ऐसी हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है लेकिन इस नतीजे पर भी पहुंचना सही नहीं है कि ऐसी जातियों के सभी लोग आर्थिक रूप से कमजोर और तिरस्कृत हैं अथवा उनकी सामाजिक हैसियत वही है जो अब से पचासों साल पहले हुआ करती थी। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का व्यापक असर होने की पूर्ण संभावना है। यह किसी एक प्रदेश या गठबंधन तक सीमित नहीं रहेगा. हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड के अतिरिक्त महाराष्ट्र समेत कई राज्यों से भी यह मांग उठने लगी है। इंडी अलायन्स के साथ ही एनडीए के कई घटक दल भी जाति आधारित गणना के पक्ष में खड़े हो गए हैं। जातिगत गणना के मुद्दे पर राजनीति करने वाले अधिकतर क्षेत्रीय दल हैं, जिनका परंपरागत नारा है, ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी’। स्पष्ट

है कि यह नारा अब अपने आप देश की राजनीति के केंद्र में आ जाएगा। इससे राजनीति में वर्चस्व रखने वाली जातियों की भूमिका सिमट कर सीमित होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि अपेक्षाकृत कम संख्या वाली जातियों के बीच से हिस्सेदारी की मांग बढ़ने लगेगी। लोकसभा विधानसभा चुनाव में वे भी अपनी आबादी के अनुरूप टिकट की मांग करने लगेंगे। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। लाभार्थी योजनाओं के विस्तार के वादों की सूची लंबी हो सकती है. साथ ही आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण की मांग भी उठने लगेगी। फिलहाल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल को अगर छोड़ दें तो बिहार की तर्ज पर अन्य राज्यों से जातिगत गणना की मांग आना शुरू हो चुकी है। सबसे मुश्किल और बड़ी मांग वाम दलों की ओर से आ रही है. भाकपा और माकपा, बिहार की तरह पूरे देश में विभिन्न जातियों की आबादी गणना कर स्थिति जानना चाहती है। बिहार में सक्रिय भाकपा माले का समर्थन तो इस मांग को पहले से ही प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा द्वारा भी पुरजोर मांग उठाई गयी है। यूपी में अपना दल के दोनों गुटों के साथ, निषाद पार्टी भी इसी रास्ते पर है। राजभर की पार्टी सुहेलदेव भी इसकी प्रबल पक्षधर है। राहुल गांधी ने तो पहले ही घोषणा कर रखी है कि अगर कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आती है तो जातिगत गणना कराई जाएगी क्योंकि बीमारी का पता लगाने के लिए एक्सरे जरूरी है। एनडीए के सहयोगी दल भी मुखर होने लगे हैं। बिहार में एनडीए के साथी तीनों दलों लोजपा के दोनों और जीतना मम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोचा ने भी बिहार की तर्ज पर देश में जातिगत गणना की मांग कर दी

है। रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का बयान भी इसके पक्ष में ही आया है। महाराष्ट्र में सक्रिय अजीत पवार एवं एकनाथ शिंदे की पार्टी ने भी इस मांग की पुर्जोर सिफारिश कर दी है। जहां तक दक्षिण भारत में डीएमके का प्रश्न है, वह तो इस अवधारणा की जन्मदाता ही है। इस मांग का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह होगा कि मंडल आरक्षण के दूसरे दौर की सियासत शुरू हो जाएगी और इसके सहारे आरक्षण की अधिकतम 50% की संवैधानिक सीमा की बाध्यता को हटाने की मांग एक बार फिर तेज हो जायगी। विपक्षी खेमे का यह ब्रह्मास्त्र भाजपा के लिए 2024 में इसलिए भी चुनौती बन सकता है क्योंकि उत्तर के राज्यों में सियासत को ओबीसी फैक्टर प्रभावित करता ही है। सपा, राजद और जेडीयू जैसी पार्टियां यह जानती हैं कि ओबीसी वर्ग के भाजपा के साथ जाने के बाद उनकी राजनीतिक ताकत घट गयी है। सीएसडीएस जैसी एजेंसियों के आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे के कारण भाजपा के ओबीसी वोट में करीब दो गुना वृद्धि हुई थी और 2019 में इस आंकड़े में और इजाफा हुआ। विपक्षी पार्टियों के लिए ओबीसी के जा चुके आधार को वापस पाने के लिए जातीय जनगणना एक मजबूत हथियार के रूप में देखा जा रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के जरिए संसद व विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के भाजपा के दावों के बढ़ते जनाधार को रोकने के लिए विपक्ष ने ओबीसी व जातीय गणना का तुरुप चलने का संदेश लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान दे ही दिया था। यह अब और अधिक जोर शोर के साथ उठाया जा सकता है।

**सुनील कुमार महला**

खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। जानकारी देना चाहूंगा कि भारत ने कनाडा के आरोपों को सिरि से खारिज कर दिया था। हाल ही में, कनाडा और भारत के बीच तल्ख होते रिश्तों के बीच अब बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं। मीडिया के हवाले से यह पता चलता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो ने अब यह बात कही है कि भारत व कनाडा के बीच रिश्ते काफी पुराने हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ रिश्तों का अपना महत्व है और कनाडा रिश्तों को बेहतर बनाएगा। इस मामले में कनाडा काफी गंभीर है। वैसे कनाडा पर हर तरफ से दबाव भी इन दिनों बढ़ रहा है।

एलन मस्क ने हाल ही में कनाडा सरकार की दुनिया की सबसे दमनकारी ऑनलाइन सेंसरशिप योजना लेकर यह कहा है कि जस्टिन अभिव्यक्ति व आजादी को दबा रहे हैं। एलन मस्क स्पेसएक्स के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक हैं। मस्क ने टूडो सरकार की आलोचना की है। यहां यह बात महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय है कि कनाडा ने एक आदेश के तहत सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं को

आधिकारिक रूप से सरकार के रिकॉर्ड में पंजीकृत कराने का आदेश दिया है ताकि सरकार उस पर रेगुलेटरी कंट्रोल कर सके। वास्तव में कनाडा सरकार के इस आदेश की चमकर आलोचना की जा रही है। पत्रकार और लेखक ग्लेन ग्रीनवालड ने सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक पोस्ट साझा की है जिसमें उन्होंने यह लिखा कि कनाडा सरकार दुनिया की सबसे दमनकारी ऑनलाइन सेंसरशिप योजना लेकर आई है। वास्तव में इसके तहत सभी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं पर रेगुलेटरी नियंत्रण कर सके।

यह भी उल्लेखनीय है कि यह पहली बार नहीं है कि कनाडा की टूडो सरकार पर बोलने की आजादी के हनन का आरोप लगा हो। इससे पहले भी फरवरी वर्ष 2022 में भी टूडो सरकार ने अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके बाद भारत ने संपूर्ण दुनिया के सामने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, जिसका बहुत ही सकारात्मक व जोरदार असर पड़ा। कनाडा के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी भारत-कनाडा के बीच तनातनी को उचित नहीं माना है।

असम सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए सभी 2,197 ग्राम पंचायत सचिवों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह रोकथाम अधिकारी के रूप में नामित किया है। ये अधिकारी ही पॉक्सो एक्ट के उन मामलों में शिकायत दर्ज कराएंगे जहां लड़की की उम्र 14 साल से कम है।अगर आंकड़ों के आइने में देखें तो असम सरकार का फैसला स्वागतयोग्य प्रतीत होता है। कुछ समाजसेवी संगठनों ने भी इसे सराहा है हालांकि दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है जो इस फैसले को संदेहास्पद दृष्टि से देख रहा है। राज्य के कुछ हिस्सों में इस फैसले के खिलाफ लोग खुला-प्रदर्शन में भी जुट गए हैं। इन्हें आशंका है कि मुस्लिमों को परेशान करने के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है।

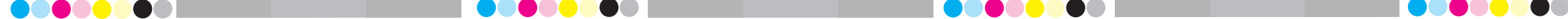
दरअसल, मुस्लिम समुदाय में बाल विवाह का प्रचलन अधिक है। हालांकि मुस्लिमों को वोट बैंक के रूप में देखने वाले राजनीतिक दल इस तथ्य को सिरि से नकार देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका वोट बैंक उनसे छिटक जाएगा और सत्ता की चाबी उनसे दूर हो जाएगी। असम में फैसले के विरोध के पीछे भी यही राजनीतिक कारण है।यह देश का दुर्भाग्य है कि कई बार ऐसे फैसलों का भी विरोध किया जाने लगता है जो कि समाज के हित में हों। अधिकांश मामलों में राजनीतिक नफा-नुकसान देखकर पार्टियां बेवजह विरोध में उतर आती हैं जबकि इस फैसले के देशहित में दूरगामी परिणाम होंगे। गौरतलब है कि यहां पर बीते साल हुए एक देशव्यापी आंदोलन का जिक्र करना लाजिमी है।

# दबाव के बाद कनाडा का यू टर्न

विरोध प्रदर्शन किया था और उस समय इसे लेकर कनाडा में बहुत हंगामा हुआ था। तब हालात को नियंत्रित करने के लिए कनाडा सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया था।

बहरहाल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अपने अमेरिकी दौरे के दौरान यह बात कही थी कि कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जहां भारत से संघटित अपराध, लोगों की तस्करी के साथ ही, अलगाववाद और हिंसा का मेल है।एस जयशंकर ने यह बात कही है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने जिस तरह निजी और सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया, वो ठीक नहीं था। उन्होंने कहा कि कनाडा को खालिस्तानियों पर लगाम लगानी चाहिए। भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा जस्टिन टूडो ने यू-टर्न लिया और कहा कि वैश्वक स्तर पर आज भारत का महत्व बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरी है कि कनाडा और उसके सहयोगी भारत के साथ मिलकर काम करें। हैरानी की बात है कि भारत पर गंभीर आरोप लगाने के बाद अब खुद जस्टिन टूडो भारत को महाशक्ति बताकर दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जाने की पैरोकारी कर रहे हैं।

खैर जो भी हो निज्जर मामले में कनाडा की अनावश्यक आक्रामकता के बाद भारत ने एक के बाद एक कड़े व सख्त कदम उठाकर कनाडा को यह जता दिया है कि भारत पर वैश्वक दबाव चलने वाला नहीं है। यहां पाठकों को यह बताया जाना आवश्यक है कि निज्जर कनाडा में एक प्रमुख खालिस्तान समर्थक नेता थे और खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) का हेड था। भारत के गृह मंत्रालय ने केटीएफ पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विदेशी स्रोतों से फंडिंग और हथियारों के उपयोग का आरोप लगाया था। भारतीय अधिकारी कई वर्षों तक निज्जर को ट्रैक कर रहे थे। इसी साल 18 जून को कनाडा में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से निज्जर के समर्थक भारत को उसकी हत्या में शामिल बता रहे हैं। कनाडा ने भारत पर बहुत ही गलत आरोप लगाए हैं, जो कि ठीक नहीं है। कनाडा के आरोपों के बाद भारत ने कनाडा की कार्रवाई के जवाब में कनाडा के राजनयिकों को वापस भेजा, फिर कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके बाद भारत ने संपूर्ण दुनिया के सामने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, जिसका बहुत ही सकारात्मक व जोरदार असर पड़ा। कनाडा के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी भारत-कनाडा के बीच तनातनी को उचित नहीं माना है।







# जीवित्पुत्रिका व्रत कल, संतान की सुरक्षा के लिए रखते हैं कठिन निर्जला व्रत



## जीवित्पुत्रिका व्रत 2023 पूजा मुहूर्त

**6 अक्टूबर को जितिया व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 06 बजकर सुबह 10 बजकर 41 मिनट तक है. इसमें चर-सामान्य मुहूर्त सुबह 06:16 बजे से सुबह 07:45 बजे तक है. उसके बाद लाभ-उन्नति मुहूर्त सुबह 07:45 बजे से सुबह 09:13 बजे तक है. अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 09:13 बजे से सुबह 10:41 बजे तक है. उस दिन का अभिजित मुहूर्त 11:46 एएम से 12:33 पीएम तक है।**

**आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर को सुबह 06 बजकर 34 मिनट पर होने वाला है।** जीवित्पुत्रिका व्रत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त प्रातः 06 बजकर सुबह 10 बजकर 41 मिनट तक है।

जीवित्पुत्रिका व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जितिया को जीवित्पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया व्रत में गंधर्व राजा जीमूतवाहन की पूजा होती है और जितिया व्रत कथा सुनते हैं। राजा जीमूतवाहन ने पक्षीराज गुरुड़ से नागमाता के पुत्रों की रक्षा की थी।

इस वजह से माताएं जितिया व्रत में जीमूतवाहन से अपनी संतान की सुरक्षा, सभी संकटों से मुक्ति देने और उनके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। कब है जीवित्पुत्रिका व्रत?

पंचांग के अनुसार, इस साल आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सुबह 06 बजकर 34 मिनट पर होने वाला है और इस तिथि की मान्यता 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 08 बजकर 08 मिनट तक है। ऐसे में जितिया व्रत 7 अक्टूबर को रखा जाएगा।

**सर्वार्थ सिद्धि समेत 2 शुभ योग में जितिया व्रत** इस साल जीवित्पुत्रिका व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और परिघ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग रात में 09 बजकर 32 मिनट से बन रहा है, जो पारण वाले दिन 7 अक्टूबर को सुबह 06 बजकर 17 मिनट तक है।

वहीं परिघ योग सुबह से लेकर अगले दिन प्रातः 05 बजकर 31 मिनट तक है। व्रत के दिन आर्द्रा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 09 बजकर 32 मिनट तक है, उसके बाद से पुनर्वसु नक्षत्र है।

**जीवित्पुत्रिका व्रत की पूजा विधि**

जिन माताओं को जितिया व्रत रखना है, वे व्रत पूर्व से सात्विक भोजन करें। व्रत वाले दिन प्रातःकाल में स्नान आदि के बाद जीवित्पुत्रिका व्रत और पूजा का संकल्प करें।

यह आपको निर्जला व्रत करना है। पूजा मुहूर्त में कुश से निर्मित जीमूतवाहन की मूर्ति की स्थापना पानी से भरे एक पात्र में करें। इसके बाद अक्षत, फूल, माला, सरसों तेल, खल्ली, बांस के पत्ते, धूप, दीप आदि से जीमूतवाहन की पूजा करें। उन पर लाल और पीले रंग की रूई अर्पित करें।

फिर मिट्टी और गोबर से बनी मादा चील और मादा खियाह की मूर्ति पर सिंदूर, केराव, सीरा, दही और चूड़ा चढ़ाएं। उसके बाद जितिया व्रत की कथा सुनें। संतान की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करें। फिर अगले दिन स्नान आदि के बाद पारण करके व्रत को पूरा करें।

**- मुकेश ऋषि**

## श्राद्ध से पितृ खुश हैं या नहीं? ऐसे मिलेंगे शुभ संकेत

पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में सनातन धर्म को मानने वाले लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई प्रकार के उपाय कर रहे हैं। कोई पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर रहा है, तो कोई ज्योतिष द्वारा बताए गए उपाय करके अपने-अपने पितरों को प्रसन्न कर रहा है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक, पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिवारजन के बीच आते हैं। इस दौरान पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ पक्ष में पिंडदान, कर्मकांड, श्राद्ध इत्यादि क्रम भी किए जाते हैं।

पितृपक्ष में पितृ दोष लगने पर परिवार में कलह की स्थिति भी पैदा होती है। वहीं, दूसरी तरफ पितृ के प्रसन्न रहने पर परिवार में सदस्यों के मध्य स्नेह और प्यार बना रहता है।

मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ के प्रसन्न रहने पर कौवा भोजन करने घर आते हैं, लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि पितृ पक्ष के दौरान अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं, तो उसके पहले आपको भी कुछ संकेत प्राप्त होते हैं।

**जातक को मिलते हैं संकेत** अयोध्या के ज्योतिषी पंडित कल्कि राम के मुताबिक, पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में पितृ आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं।

पितृपक्ष के दौरान अगर पितृ प्रसन्न हैं, तो जातक को कुछ संकेत मिलते हैं। अगर पितृपक्ष में आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं, तो आपके परिवार के बीच प्यार और स्नेह बना रहेगा। एक दूसरे का सहयोग मिलेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

## पितृ पक्ष में गलती से भी न करें 5 काम

पितृ पक्ष के समय में पितरों को खुश करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। लेकिन आपकी कुछ आदतों या कामों के वजह से पितर नाराज भी हो सकते हैं। इससे वे आपको श्राप दे सकते हैं, जिससे आपका जीवन अशांति, कष्ट और दुख से भर सकता है। परिवार में कलह और काम में



रुकावटें आ सकती हैं। परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। आपस में प्रेम का अभाव हो सकता है और घर में कलह से दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। पितृ पक्ष या फिर किसी भी दिन आप पितरों का अपमान न करें। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणि भट्ट से जानते हैं कि पितृ पक्ष में कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

**पितृ पक्ष में न करें ये गलतियां**

**1.छौड़ कर्म**

पितृ पक्ष के समय में छौड़ कर्म भूलकर भी नहीं करना चाहिए। छौड़ कर्म में दाढ़ी, बाल, नाखून काटना आता है। पितृ पक्ष में दाढ़ी, बाल, नाखून आदि काटने से दोष लगता है। इससे पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

**2. असमय और अकारण यात्रा**

शास्त्रों के अनुसार, पितृ पक्ष के समय में असमय और अकारण यात्रा करना वर्जित बताया गया है। बिना उद्देश्य की यात्रा न करें। जिस दिन यात्रा करना जरूरी है तो मुहूर्त देखकर घर से निकलें और दिशाशूल

## पितरों के भोजन में खीर-पूड़ी ही क्यों बनाई जाती है?

पितृ पक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 से हो चुका है। श्राद्ध-कर्म में तर्पण को सबसे अहम अंग माना गया है। तत्पश्चात, श्रद्धानुसार भोजन बनाकर कराना दूसरा अहम अंग है। तीसरा अंग है त्याग। वही श्राद्ध का भोजन बहुत ही साधारण तथा शुद्ध होना चाहिए। श्राद्ध के खाने में खीर-पूड़ी जरूर बनाएं। खीर को पायस अन्न कहते हैं, पायस यानी प्रथम भोग। दूध तथा चावल से बनी खीर शरीर को ऊर्जा देती है। यही कारण है कि पितृ पक्ष पितरों को खीर, पूड़ी का धूप देते हैं तथा पितरों के नाम ब्राह्मण भोज कराते हैं।



\* श्राद्ध का खाना बनाते वक़्त जौ, मटर और सरसों का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ माना जाता है। पितरों की भोग की थाल में कद्दू की खट्टी-मिठी सब्जी अवश्य सम्मिलित की जाती है।

\* पितरों के भोजन में तिल का अवश्य

इस्तेमाल करें। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। तिल को बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। प्रसाद में अधिक से अधिक तिल होने पर उसका अक्षय फल प्राप्त होता है।

\* पितृ पक्ष में चना, मसूर, उड़द दाल, प्याज, लहसुन, मूली से युक्त भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसे अशुभ माना गया है।

\* श्राद्ध के भोजन से सबसे पहले अग्नि में धूप दें, फिर पंचवालि ग्रास निकालें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण न मिलें तो बहन, दामाद या भानजे को भी भोजन कराना बहुत लाभदायक होता है।

## अक्टूबर में 5 राशिवाले रहें सावधान !

अक्टूबर का महीना 5 राशि के जातकों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। वृष, कन्या समेत 5 राशिवालों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है तो कुछ को नौकरी और बिजनेस में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लापरवाही के कारण नौकरी जाने का डर रहेगा। सड़क पर ध्यान से वाहन न चलाने के कारण दुर्घटना की आशंका है। कुछ लोगों के विरोधी भी प्रबल होंगे, जो आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आइए जानते हैं कि अक्टूबर महीने में कितन 5 राशिवालों को सावधान रहना है और उन पर क्या नकारात्मक असर हो सकता है।

वृष- यह महीना आपको काफी व्यस्त रखेगा। काम को लेकर आपकी काफी भागदौड़ रहेगी। आपको सुदूर क्षेत्रों में जाने का मौका मिलेगा। आपको इस महीने अपने साथ काम करने वाले लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपके कुछ विरोधी प्रबल होंगे, जो आपको परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। इस कारण आप मानसिक रूप से भी तनावग्रस्त रहेंगे। यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको किसी खूबसूरत जगह घूमने जाने का मौका मिलेगा।

बिजनेस में उत्तम सफलता के योग बनेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। आपको पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत के प्रति लापरवाही ना बरते।

**कन्या-** यह महीना आप पूरी तरह आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना कर पाएंगे। हालांकि, आप

ओवरकॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय भागदौड़ का रहेगा। बिजनेस करने वालों को अभी थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। अपने किसी विरोधी से इस समय सतर्क रहें। हालांकि वह आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ा देंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपके अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। सेहत को नजरअंदाज न करें, नहीं तो बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। अपने खान-पान का ध्यान रखें। आपको बुखार हो सकता है या पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं।

**धनु-** अक्टूबर का महीना आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। नौकरी में ओवरकॉन्फिडेंट होने से बचें। किसी भी कंट्रोवर्सी से दूर रहें। अभी आपके कुछ गुप्त रूप से खचें भी होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो अभी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत होगी। ज्यादा तेल मसाले वाले भोजन से दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा।

**मकर-** नौकरीपेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा कमजोर है। नौकरी में तबादले के योग भी बन सकते हैं। ध्यान से काम न करने के कारण नौकरी जा भी सकती है, इसलिए थोड़ी सावधानी जरूर रखें। जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में आपका ध्यान रहेगा और आपको कोई संपत्ति प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह महीना आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है। अपनी दिनचर्या का पालन करें और योग व प्राणायाम को इसमें शामिल करें।

## बिहार के गया में ही क्यों होता है पिंडदान और मिलता है मोक्ष

बिहार के गयाजी में पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए पिंडदान की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। कहा जाता है कि गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिनों तक का समय पितृपक्ष का होता है। मान्यता के अनुसार पिंडदान मोक्ष प्राप्ति का एक सहज और सरल मार्ग है। मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण होते हैं। माता-पिता की सेवा करके मरणोपरांत पितृपक्ष में पूर्ण श्रद्धा से श्राद्ध करने पर पितृऋण से मुक्ति मिलती है।

ऐसे तो देश के हरिद्वार, गंगासागर, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट, पुष्कर सहित कई स्थानों में भगवान पितरों को श्रद्धापूर्वक किए गए श्राद्ध से मोक्ष प्रदान कर देते हैं, लेकिन गया में किए गए श्राद्ध की महिमा का गुणगान तो भगवान राम ने भी किया है। कहा जाता है कि भगवान राम और सीताजी की सेवा करके मरणोपरांत पितृपक्ष में पूर्ण श्रद्धा से श्राद्ध करने पर पितृऋण से मुक्ति मिलती है।

यह मोक्ष की भूमि कहलाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार गया जाने के लिए घर से निकले एक-एक कदम पितरों को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए सीढ़ी बनाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार गया में पूर्ण श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृ देवता के रूप में उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहते हैं।



जानिए गयासुर की कहानी मान्यता है कि गया भस्मासुर के वंशज दैत्य गयासुर की देह पर फैला है। कहते हैं कि गयासुर ने ब्रह्माजी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर वरदान मांगा कि उसकी देह देवताओं की भांति पवित्र हो जाए और उसके दर्शन से लोगों को पापों से मुक्ति मिल जाए।

वरदान मिलने के पश्चात स्वर्ग में जन्मस्वस्था बढ़ने लगी और लोग अधिक पाप करने लगे। इन पापों से मुक्ति के लिए वे गयासुर के दर्शन कर लेते थे। इस समस्या से बचने के लिए देवताओं ने गयासुर से कहा कि उन्हें यज्ञ के लिए पवित्र स्थान दें। गयासुर ने देवताओं को यज्ञ के लिए अपना शरीर दे दिया। कहा जाता है कि दैत्य गयासुर जब लेटा तो उसका शरीर पांच कोस में फैल गया।

यही पांच कोस का स्थान आगे चलकर गया के नाम से जाना गया। गया के मन से लोगों को पाप मुक्त करने की इच्छा कम नहीं हुई, इसलिए उसने देवताओं से फिर वरदान की मांग कि यह स्थान लोगों के लिए पाप मुक्ति वाला बना रहे। जो भी श्रद्धालु यहां श्रद्धा से पिंडदान करते हैं, उनके पितरों को मोक्ष मिलता है।

**गया में ही पिंडदान करने का खासा महत्व क्यों है ?**

वे कहते हैं कि फल्गु नदी के तट पर पिंडदान किए बिना पिंडदान हो ही नहीं सकता। गया में पहले विभिन्न नामों की 360 वेदियां थीं, जहां पिंडदान किया जाता था। इनमें से अब 48 ही बची हैं। वर्तमान समय में इन्हीं वेदियों पर लोग पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। पिंडदान के लिए प्रतिवर्ष गया में देश-

विदेश से लाखों लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि हर इंसान की यह इच्छा होती है कि मरने के बाद गया धाम में उसका पिंडदान किया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके।

**गया तीर्थ में जलरूप में विराजमान है विष्णु** पितृपक्ष के पहले दिन की शुरुआत पावन फल्गु नदी के जल में पितरों को तर्पण करने के साथ होती है। एक पखवारे तक चलने वाले पितृपक्ष मेले की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। फल्गु तीर्थ और विष्णुपद में तादात्म्य संबंध है। भगवान विष्णु भी गया तीर्थ में जल रूप में विराजमान हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में किसी भी एक व्यक्ति का पैर फल्गु में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा गया कि फल्गु सर्वनाश और गदाधर देव का दर्शन एवं गयासुर की परिक्रमा ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति दिलाती है। गयासुर की परिक्रमा का अभिप्राय समस्त पिंडवेदियों से है, क्योंकि एक कोशिश का मतलब तीन किलोमीटर ( पंचकोश गया क्षेत्र) के क्षेत्र से है, जिसमें मुख्य वेदियां सम्मलित हैं। फल्गु तीर्थ के और भी कई पक्ष हैं, जिसके कारण इसकी आध्यात्मिकता बढ़ी है। बोधगया से उत्तर निरंजना संगम के पश्चात इसका उत्तरवाही अस्तित्व स्वतंत्र है। यह पुनपुन नदी से भी अपने को अलग रखकर आहर में खो जाती है। धार्मिक गौरव में यह गंगा से कम नहीं है। गंगा को सुर सरिता भले कहा गया है, पर फल्गु तो स्वयं विष्णु का अवतरण ही है।

































## इस बार वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी

बीसीसीआई ने कहा- हमने कभी नहीं कहा कि उद्घाटन समारोह होगा; कैप्टेंस डे सेरेमनी होगी

अहमदाबाद, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। बीसीसीआई सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर भास्कर को बताया कि इस बार वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। 4 अक्टूबर को कैप्टेंस डे सेरेमनी या पेरेंड होनी है। यह पहले से तय प्रोग्राम के मुताबिक ही होगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह सेरेमनी होगी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक टूर्नामेंट में क्लोनिंग सेरेमनी जरूर होगी। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के मैच के पहले भी एक स्पेशल इवेंट होस्ट किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।

बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक ओपनिंग सेरेमनी का तो कोई प्लान ही नहीं था। लिहाजा इसे कैंसिल किए जाने का सवाल ही नहीं उठता।



**4 अक्टूबर को होनी थी ओपनिंग सेरेमनी**

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड कप 2023 की ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी 4 अक्टूबर को होनी थी। इसके अगले दिन यानी पांच अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा। फैंस को भी इस ओपनिंग सेरेमनी का बेसब्री से इंतजार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपनिंग

सेरेमनी में बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह, सिंगर अरिजीत सिंह, एक्स्ट्रेस तमन्ना भाटिया, सिंगर श्रेया घोषाल और लिजेंड्री सिंगर आशा भोसले परफॉर्म करने वाली थीं। इसके अलावा आतिशबाजी और लेजर शो भी होना था।

4 अक्टूबर को कैप्टेंस डे पेरेंड जरूर होगी। इस दौरान वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली सभी 10 टीमों

के कप्तान अपने-अपने देश की जर्सी में मौजूद रहेंगे। इस फंक्शन के बाद सभी कप्तान उन शहरों के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां उनकी टीमों को पहला मुकाबला खेलना है।

**खालिस्तानी आतंकी पन्नु ने धमकी दी थी**

सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नु ने भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर धमकी दी थी।

कुछ दिन पहले उसकी तरफ से एक ऑडियो जारी किया गया था। इसमें उसने कहा था- 5 अक्टूबर को क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं, आतंकवाद वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच के दिन खालिस्तानी झंडों का सैलाब आएगा। हमारे साथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लिया जाएगा।

## आईसीसी ने सचिन को वर्ल्डकप का ग्लोबल ब्रांड एम्बेस्डर बनाया

## तेंदुलकर बोले- वर्ल्ड कप की मेरे दिल में खास जगह

दुबई, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। सचिन तेंदुलकर वनडे वर्ल्ड कप के ग्लोबल ब्रांड एंबेस्डर बनाए गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन्हें यह सम्मान दिया। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। तेंदुलकर यहां ट्रॉफी लेकर पहुंचेंगे। इसके बाद वर्ल्ड कप का आगाज होगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों टीम 2019 वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट हैं।

2011 वर्ल्ड कप जीतना सबसे गौरवपूर्ण पल रहा। ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने के बाद सचिन ने कहा- वर्ल्ड कप का मेरे दिल में खास स्थान रहा है। 1987 में बॉल बॉय से लेकर 6 बार देश का



प्रतिनिधित्व करना और 2011 का वर्ल्ड कप जीतना मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण पल रहा। भारत में हो रहे विश्व कप में इतनी टीमों और खिलाड़ी मजबूती से लड़ने वाले हैं। मैं इस टूर्नामेंट को लेकर उत्साहित हूं। मुझे उम्मीद है कि

यह एडिशन बच्चों को खेलों में आने और देश का प्रतिनिधित्व करने की प्रेरणा देगा।

विव रिचर्ड्स, डिविलियर्स और मुथैया मुरलीधरन भी ब्रांड एंबेस्डर

आईसीसी ने विवियन रिचर्ड्स,

एबी डिविलियर्स, ऑफन मॉर्गन, एरोन फिंच, मुथैया मुरलीधन, रॉस टेलर, सुरेश राय, मिताली राज और मोहम्मद हफीज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।

6 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा रहे तेंदुलकर

सचिन तेंदुलकर 6 वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा रहे। उन्होंने 1992 से 2011 तक 45 वर्ल्ड कप मैचों में देश कका प्रतिनिधित्व किया। इन मैचों में तेंदुलकर ने 56.95 के एवरेज से 2278 रन बनाए। इनमें 6 सेंचुरी और 15 हाफ सेंचुरी शामिल हैं।

भारत का पहला मैच 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। यह मुकाबला चेन्नई के चेर्पाक स्टेडियम में खेला जाएगा।

## क्या 2023 में खत्म होगा भारतीय फैंस का ट्रॉफी का इंतजार ? कप्तान रोहित ने दिया जवाब



मुंबई, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। वनडे विश्व कप 2023 के लिए सिर्फ एक दिन बचा है, रोहित शर्मा एंड कंपनी से ट्रॉफी के सूखे को तोड़ने की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं।

भारत को आईसीसी ट्रॉफी पर कब्ज़ा जमाए हुए एक दशक से

अधिक समय हो गया है। जब भारत ने 2013 में एमएस धोनी के नेतृत्व में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी तब रोहित शर्मा उस टीम का हिस्सा थे।

2013 से, भारत तीनों प्रारूपों में नौ आईसीसी आयोजनों का हिस्सा रहा है, लेकिन वे आईसीसी

ट्रॉफी जीतने में असफल रहे हैं। कुछ विशेषज्ञ तो भारत को नया चोकर्स भी कहने लगे हैं। अब, वनडे विश्व कप 2023 के लिए सिर्फ एक दिन बचा है, रोहित शर्मा एंड कंपनी से ट्रॉफी के सूखे को तोड़ने की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं।

**क्या भारत जीतेगा 2023 का विश्वकप ?**

भारत घरेलू विश्व कप खेल रहा है, इसलिए रोहित और टीम पर काफी दबाव है। क्या इस साल भारत आखिरकार तीसरी बार विश्व कप जीतेगा ? जब रोहित शर्मा से पूछा गया कि क्या भारत में इतनी दूर तक जाने की क्षमता है, तो कप्तान ने बहुत ही कूटनीतिक जवाब दिया।

खेल डेस्क, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत से पहले अफगानिस्तान ने अपनी मजबूती का प्रमाण दिया है।

भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। दरअसल वार्म-अप मैच में अफगानिस्तान की टीम ने 1996 वर्ल्ड कप की चैंपियन श्रीलंका को मात दे दी है। इस प्रकार अफगानिस्तान ने बता दिया है कि उन्हें भी विश्वकप में हल्के में नहीं लिया जा सकता।

बाकिश से प्रभावित मैच में श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। टीम की तरफ से कुशल मेंडिस के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ कमाल नहीं कर सका जिसके चलते उन्होंने बोर्ड पर



46.2 ओवर में 294 रन बनाए। वहीं बाद में बारिश के चलते अफगानिस्तान को 42 ओवर में 257 रनों का लक्ष्य मिला जिसे उन्होंने आसानी से हासिल कर लिया।

**ऐसी रही श्रीलंका की पारी**

पहले बल्लेबाजी करते हुए,

दिमुथ करुणार्त्ते के जल्दी आउट होने के बाद मेंडिस क्रीज पर आए और तेजी से अपनी लय में आ गए। वह तेजी से 59 गेंदों में शतक बनाने में सफल रहे।

19 चौकों और छह छकों सहित 158 के स्कोर पर मेंडिस 30वें ओवर की समाप्ति पर रिटायर हुए।

इसके बाद अफगानिस्तान ने गेंद से जलवा बिखेरा। मोहम्मद नबी ने 4/44 का स्पेल डाला जिससे श्रीलंका 22 गेंदें शेष रहते ही 294 पर ऑलआउट हो गई।

**ऐसी रही अफगानिस्तान की पारी**

कसुन राजिथा ने खराब

## भारत ने पहली बार 70 से ज्यादा पदक जीते

हांगझोऊ, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। भारत ने 2018 में इजोनेशिया में हुए

एशियाई खेलों में कुल 70 पदक जीते थे। यह अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 11वें दिन की शुरुआत में ही 71वां पदक हासिल कर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

2023 एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। 11वें दिन की सुबह भारत की झोली में दो पदक आए। पहला पदक 35 किलोमीटर दौड़ में था और दूसरा पदक तीरंदाजी में था। शुरुआती 10 दिन में 69 पदक हासिल करने वाले भारत ने 11वें दिन 71 का जादुई आंकड़ा छुआ और पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। एशियाई खेलों के इतिहास में यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले कभी भी भारत ने एशियाई खेल में 71 पदक नहीं जीते थे। ज्योति सुरेखा और ओजस देवतले की जोड़ी ने मिश्रित तीरंदाजी प्रतियर्स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल कर भारत को 71वां पदक दिलाया। आइए जानते हैं अब तक एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है।

एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में हुई थी। दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और दामोे उन्होंने पूरे 80 अंकों हासिल किए। वहीं, तेजस एक प्रयास में नौ ही अंक हासिल कर पाए थे। उन्होंने अपने आठ प्रयासों में 79 अंक हासिल किए।

## भारत बनाम दक्षिण कोरिया हॉकी: भारत ने कोरिया को 5-3 से हराया

### फाइनल में जगह बनाई; रजत पदक पक्का किया

प ह ला गोल: भारत के लिए पहला गोल पांचवें मिनट में आया। भारतीय टीम के पहले शॉट को कोरियाई गोलकीपर ने रोक लिया, लेकिन गेंद वापस हार्दिक सिंह के पास आ गई।

उन्होंने रिबाउंड पर कोई गलती नहीं की और गेंद को गोलपोस्ट में डाल दिया।

**दूसरा गोल:** टीम इंडिया ने दूसरा गोल 11वें मिनट में किया। गुरजंत ने लॉन्ग बॉल को संभाला और कोरिया के डी में पहुंच गए। उन्होंने गोलपोस्ट के पास खड़े मनदीप सिंह को पास कर दे दिया। मनदीप ने बिना कोई गलती किए गोल कर दिया।

**तीसरा गोल:** भारत के लिए



कोरिया ने अपना पहला गोल किया। पेनल्टी कॉर्नर पर फायदा उठाते हुए उसने मैच में अपना खाता खोला। कोरिया के लिए जूंग मानजाई ने पहला गोल किया।

**पांचवां गोल:** 20वें मिनट में कोरिया ने अपना दूसरा गोल दागा। जुंग माजी ने एक बार फिर कमाल किया और अपनी टीम की वापसी कराई।

**छठा गोल:** 24वें मिनट में अमित रोहदास ने भारत के लिए चौथा गोल किया और टीम इंडिया को मैच में काफी आगे कर दिया। सातवां गोल: 42वें मिनट में कोरिया के लिए जुंग माजी ने तीसरा गोल किया और भारत की बढ़त कम की।

**आठवां गोल:** 54वें मिनट में अभिषेक ने गोल कर भारत को अहम बढ़त दिलाई। अंतिम समय में

किए गए उनके गोल से भारत को दो गोल की बढ़त मिल गई, जो कि निर्णायक साबित हुई।

नौ साल बाद फाइनल में पहुंचा भारत

भारतीय टीम 2014 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची है। 2018 में भारत को सेमीफाइनल में हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद थे। भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक पर कब्ज़ा किया था। फाइनल में भारत का मुकाबला छह अक्टूबर को चीन या जापान से हो सकता है।

**गुप दौर में टीम इंडिया ने किए थे 58 गोल**

भारतीय टीम एशियाई खेलों के मौजूदा संस्करण में शानदार फॉर्म में चल रही है। उसने गुप दौर में अपने सभी पांच मैच जीते हैं। गुप दौर में टीम इंडिया ने 58 गोल दागे थे। उसके खिलाफ सिर्फ पांच गोल हुए थे। सेमीफाइनल में भी भारत ने पांच गोल किए। हालांकि, दक्षिण कोरिया भी तीन गोल करने में सफल रहा।



तीरंदाजी की मिश्रित स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह मौजूदा एशियाई खेलों में भारत को 16वां स्वर्ण था। फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 159-158 के अंतर से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आइए जानते हैं कि भारतीय जोड़ी ने कैसे स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

पहला राउंड: भारत के दोनों तीरंदाजों ने दोनों प्रयास में 10-10 अंक हासिल किए और भारत को पूरे 40 अंक मिले। वहीं, दक्षिण कोरिया के तीरंदाजों ने एक प्रयास

में नौ अंक हासिल किए। पहले राउंड के बाद स्कोर 40-39 से भारत के पक्ष में था।

दूसरा राउंड: कोरियाई जोड़ी ने पहले प्रयास किया और सभी चार तीर सटीक निशाने पर दागकर 40 अंक हासिल किए। भारतीय तीरंदाजों ने भी कोई गलती नहीं की और पूरे 40 अंक हासिल किए। दूसरे राउंड के बाद भारतीय टीम 80-79 के स्कोर से आगे रही।

तीसरा राउंड: कोरियाई तीरंदाजों ने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे 40 अंक

हासिल किए। भारत की तरफ से ओजस ने एक प्रयास में नौ अंक हासिल किए और भारत की बढ़त खत्म हो गई। तीसरा राउंड खत्म होने के बाद दोनों टीमों 119-119 के स्कोर के साथ बराबरी पर रही। चौथा राउंड: भारतीय ने पहले प्रयास किया और दोनों तीरंदाजों ने 10 अंक हासिल किए। वहीं, कोरिया के जू नौ अंक ही हासिल कर पाए। भारत के पास एक अंक की बढ़त हो गई। अपने आखिरी प्रयास में चारों तीरंदाजों ने 10 अंक हासिल किए। हालांकि, जू की गलती के चलते अंत में भारतीय टीम 159-158 के स्कोर से आगे रही और स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

भारत के लिए ज्योति ने शानदार प्रदर्शन किया और सभी आठ प्रयासों में सटीक निशाने पर तीर दागे। उन्होंने पूरे 80 अंक हासिल किए। वहीं, तेजस एक प्रयास में नौ ही अंक हासिल कर पाए थे। उन्होंने अपने आठ प्रयासों में 79 अंक हासिल किए।

### भाला फेंक में भारत को दो पदक, नीरज को स्वर्ण



हांगझोऊ, 4 अक्टूबर (एजेंसियां)। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक में स्वर्ण जीत लिया है। वहीं, भारत के ही किशोर जेना ने रजत पर कब्ज़ा जमाया है। यह एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार है जब भाला फेंक में भारत ने पहले-दूसरे स्थान पर कब्ज़ा जमाया है। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। उन्होंने 88.88 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पर कब्ज़ा जमाया। वहीं, भारत के ही किशोर जेना ने 87.54 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत हासिल किया। नीरज ने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में भी स्वर्ण जीता था। वहीं, किशोर का

यह पहला एशियाई खेल है और उन्होंने रजत पर कब्ज़ा जमाया। यह किसी भी प्रतियोगिता में जेना का पहला पदक है। जापान के गेंकी डीन 82.68 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ तीसरे स्थान पर रहे।

1951 से एशियाई खेल हो रहे हैं। यह 72 वर्षों में पहली बार है जब भारत के ही दो एथलीट ने स्वर्ण और रजत पर कब्ज़ा जमाया हो। भारत के अब एशियाई खेलों के भाला फेंक स्पर्धा में पांच पदक हो गए हैं। इन दो पदक से पहले 1951 दिल्ली एशियाई खेलों में परसा सिंह ने रजत, 1982 दिल्ली एशियाई खेलों में गुरतेज सिंह ने कांस्य और 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में नीरज ने स्वर्ण जीता था। वहीं, ऐसा भी पहली बार है जब एशियाड के पुरुषों के भाला फेंक में भारत ने दो

पदक जीते हैं।

मीटर का रहा। यह नीरज का सीजन बेस्ट श्रो है। इससे ज्यादा उन्होंने इस सीजन में श्रो नहीं किया है। वह फिर से पहले स्थान पर आ गए हैं। किशोर जेना का चौथा प्रयास 87.54 मीटर का रहा और वह दूसरे स्थान पर हैं।

नीरज और जेना दोनों का छठा श्रो फाउल रहा। अपने-अपने प्रयासों के बाद ही दोनों जश्न मनाने लगे। नीरज ने स्वर्ण और जेना ने रजत जीता। इस स्पर्धा की शुरुआत में ही गड़बड़ी आ गई थी। सबसे पहले चीनी ताइपे के सुन चेंग चाओ श्रो के लिए आए, लेकिन उनका श्रो फाउल रहा। इसके बाद नीरज श्रो के लिए आए। उन्होंने श्रो किया, पर उनका स्कोर नहीं बताया गया। इसके बाद कुवैत के अब्दुलरहमान अलजाेमी ने भी श्रो कर दिया और उनका स्कोर भी नहीं बताया गया। इसके बाद खेल को करीब 15 मिनट रोका गया। नीरज काफी देर तक अधिकारियों से बात करते हुए दिखाई दिए। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ था।

**मैच में ऐसे हुए गोल**





